● वर्ष-3
● अंक-38
रायपुर, शुक्रवार
22 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› हॉर्मोन संतुलित करने के लिए...

कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित

विदेश मंत्रालय ने कहा- पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर भारत पर लगाए गए आरोप

नईदिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान और बेतुकी कार्रवाई के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बेहद खराब दौर आ गया है। एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हां, हमने कनाडा सरकार को सूचित किया है कि हमारी पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में ताकत में समानता होनी चाहिए। उनकी संख्या कनाडा में हमारी तुलना में बहुत अधिक है... मुझे लगता है कि इसमें कमी होगी।

बागची ने कहा कि भारत शुरू से कनाडा को चरमपंथी तत्वों के प्रति चेताता रहा है। कनाडा पीएम और सरकार के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि इस निज्जर मामले में कनाडा ने भारत के साथ कोई सूचना साझा नहीं की है। कनाडा की धरती से चलने वाली भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में कई बार सबूत दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बागची ने कहा कि भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है वो सभी के लिए है। सिर्फ हिंदुओं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। भारत भारतीयों को बांट कर नहीं देखता, सभी के लिए एडवाइजरी जारी करता है। विदेश

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपने मिशनों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त है। विश्वास है की विएना संधि का पालन होगा। हमारे सुरक्षा प्रबंधों पर हम सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते। सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमारे अधिकारी वीजा आवेदन पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अस्थाई रूप से काम रोका गया है। हम समय समय पर हालत की समीक्षा करते रहेंगे और फिर आगे का निर्णय लेंगे।

छात्रों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय छात्र वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं। छात्रों को हमारी वीजा सेवा बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भारतीय छात्र हैं। फाइव आयज पर उन्होंने कहा कि हमने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। हर देश को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है। कोई हमसे सीधे कुछ पूछेगा तो हम अपनी बात रखेंगे।

भारत ने की 5 बड़ी कार्रवाई

- भारत ने ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और खालिस्तानियों पर कार्रवाई की नसीहत दी है।
- भारत ने कनाडा के राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखाया।
- कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का वीजा फिलहाल बंद कर दिया गया है।
- एनआईए की तरफ से 43 गैंगस्टर की लिस्ट जारी की गई।
- कनाडा में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई।

पाकिस्तान जैसा हो गया कनाडा-कांग्रेस सांसद

भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा बयान दिया है। भारत-कनाडा तनाव के बीच मीडिया से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में हमारी प्रधानमंत्री से इस बारे में बातचीत भी हुई है। उन्होंने

कहा कि मैं प्रधानमंत्री के समक्ष उन बातों को रखा जिसकी चिंता पंजाब के लोगों को ज्यादा है। पंजाब के लाखों बच्चे वहां पढ़ते हैं या पढ़ने जाने वाले हैं। उन्होंने वहां अपनी फीस जमा कर रखी है। अगर वीजा बंद होती है तो उसे उन पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने मुझे भरोसा दिया है इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यहां किसी पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका जहाज तो वैसे ही खटाड़ा है। उन्होंने दावा किया कि मेरे दादाजी की जिसने हत्या की थी उसका दाहिना हाथ हरदीप सिंह निज्जर था।

महिला आरक्षण को संसद की मंजूरी

- प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का जताया आभार

नईदिल्ली। देश के गौरवशाली इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले बिल को आज संसद की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को यह पहले ही लोकसभा में पास हो चुका था। आज भारी समर्थन के साथ यह राज्यसभा में भी पारित हो गया। राज्यसभा में विधायक के पक्ष में 215 वोट पड़े। इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक चर्चा में भाग लेने और इस बिल का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दे कि पिछले 27 सालों में ऐसे कई मौके आए जब इस तरह के बिल को सदन में लाने की कोशिश हुई लेकिन कभी सफलता नहीं मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन के लिए सभी सांसदों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश के जन-जन में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है यह नारी शक्ति को विशेष सम्मान है। विधायक के प्रति सभी की सकारात्मक सोच से नई ऊर्जा हासिल हुई है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है बल्कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार को उस समय पंचायत राज में 33 प्रतिशत आरक्षण लाने का श्रेय देना चाहती हूं। परिणामस्वरूप, हमने पंचायत स्तर पर विकास देखा, जहां आज कई राज्यों द्वारा प्रतिशतन्न आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है...पंचायत स्तर पर महिलाओं के योगदान को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते। यह प्रधानमंत्री के लिए विश्वास का विषय है इसलिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमने किया है। चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, तीन तलाक हो या अब महिला आरक्षण विधेयक।

धर्म-जाति के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा: प्रियंका

भिलाई। केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म और जाति के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। गुरुवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि आज राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धर्म और जाति के मुद्दों को सामने लाकर उनका ध्यान भटकाया जा सके। यह लोगों को अपनी शिकायतें न उठाने देने की एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस महासचिव गुरुवार को रायपुर पहुंचीं क्योंकि उनकी पार्टी ने राज्य चुनावों से पहले अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। उनका स्वागत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके डिप्टी टीएस सिंह देव ने किया।

भिलाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं पूछती हूं कि अगर मोदी सरकार ही छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान धान 1200-1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहां तो उनकी ही सरकार है। आवारा पशु से लोग परेशान हैं। अपनी खेती की रखवाली के लिए लोगों को पूरी रात खेत में बैठना पड़ रहा है। हमने यह समस्या छत्तीसगढ़ में हल की है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 1955 में भिलाई में स्टील प्लांट की नींव डाली थी। या कहें तो आधुनिक भारत की नींव यहीं पड़ी थी। भिलाई, देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहां खड़े होकर हर देशवासी को गर्व महसूस होना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां मंच पर आने से पहले मैंने कुछ महिलाओं से बात की, उनको आत्मनिर्भर देखकर मुझे काफी गर्व हुआ। वह साहस और खुशी से मुस्कुरा रही थीं कि सरकार ने उनके लिए कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वह अपने पैरों पर खड़ी हैं। कई महिलाओं ने कहा कि वह पहली बार रोजगार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों के एक हाथ में संस्कृति का कलश है, तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जी20 का आयोजन किया, यह अच्छी बात है...लेकिन वे आपको इसका जवाब नहीं दे सकते कि बेरोजगारी, महंगाई क्यों है या किसानों को उनकी फसल के लिए जरूरी रकम क्यों नहीं मिल रही...? छत्तीसगढ़ सरकार राजनीति के पुराने तरीके का पालन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार गरीबों का अधिकार छीन रही है और अपने अमीर दोस्तों को दे रही है।

महिलाओं को सशक्त बनाने छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई अनेक योजनाएं

छत्तीसगढ़ का नेतृत्व सेवाभावी है। वो आपके आज और कल दोनों को बुलंद बनाने काम कर रहा है। भूपेश सरकार की योजनाएं महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ महतारी आज हर मंच में पूजी जा रही हैं। उनके एक हाथ में संस्कृति का कलश है और दूसरे हाथ में तकनीक है। छत्तीसगढ़ महतारी की समृद्धि के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। यह बात श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित विशाल महिला समृद्धि सम्मेलन के अवसर पर कही।

प्रमुख समाचार

वेणुगोपाल से सभापति धनखड़ ने होमवर्क कर आने कहा

नईदिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अपमान है कि राष्ट्रपति और

उपराष्ट्रपति नई संसद के उद्घाटन में मौजूद नहीं थे। धनखड़ ने कहा, हम कमियों पर समझौता नहीं कर सकते। हम दूसरों की अज्ञानता का व्यापार नहीं कर सकते। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को देश में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अथवा चेयरमैन का पद अपेक्षानुसार उनके स्तर का ही रखना होगा और वही किया गया। और पिछले तीन दिनों में भी आपने यही देखा है। जगदीप धनखड़ ने प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य के रूप में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपना होमवर्क अवश्य करें। पता लगाना। जब आप राष्ट्रपति को भी लाते हैं तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाता। उन्होंने कहा कि संविधान पढ़ें और आप पाएंगे कि भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करेंगे, यही संविधान में मूल निर्देश था।

भाजपा-एआईएडीएमके के बीच कोई समस्या नहीं : अन्नामलाई

नईदिल्ली। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार की घोषणा के कुछ दिनों बाद कि बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच कोई गठबंधन नहीं है, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई समस्या नहीं है।

अन्नामलाई ने यह भी कहा कि उन्हें एआईएडीएमके के किसी भी नेता से कोई दिक्कत नहीं है। अन्नामलाई ने कहा कि एक सामान्य सूत्र है जो एनडीए में समान विचारधारा वाले दलों को जोड़ता है और वह पीएम मोदी हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए उनकी उम्मीदवारी स्वीकार की, वे एनडीए गठबंधन में हैं। अन्नामलाई ने जवाब दिया, क्या अन्नाद्रमुक इसे स्वीकार करती है? हां। अन्नामलाई ने कहा कि जिन लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, उन्हें हाथ मिलाना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि अन्नाद्रमुक और भाजपा अलग-अलग हैं और कुछ चीजों में उनके अलग-अलग वैचारिक दृष्टिकोण हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्नाद्रमुक एकजुट राष्ट्र के लिए एक मजबूत नेतृत्व के साथ एकजुट हैं।

मध्य प्रदेश में हर तरफ व्याप्त है भ्रष्टाचार: कमलनाथ

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राजनीति लगातार जारी है। इन सब के बीच राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने गुरुवार को दावा किया कि लोग मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने

के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हर दिन एक नया घोटाला सामने आता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या फिर पीड़ित। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? अब बीजेपी को खुद ये कहने में शर्म आ रही है कि वो उनके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार ने मध्य प्रदेश के नौजवानों का वर्तमान और भविष्य दोनों छीन लिए हैं। पहले तो शिवराज सरकार ने नर्सिंग कॉलेज में मान्यता देने, फैकल्टी की नियुक्ति करने, एडमिशन करने और डिग्री देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और अब न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर अत्याचार कर रही है।

एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में महेश को जमानत

नईदिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में आरोपी 33 वर्षीय कार्यकर्ता महेश राउत को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी

(एनआईए) ने उनके खिलाफ जिन सबूतों पर भरोसा किया, वे अफवाह थे और उनकी पुष्टि नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि राउत को सीपीआई का सदस्य कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और एनआईए ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि वह प्रतिबंधित संगठन में व्यक्तियों की भर्ती में शामिल थे। पीठ द्वारा अपना आदेश सुनाए जाने के बाद एनआईए की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक संदेश पाटिल ने इस पर दो सप्ताह के लिए रोक लगाने की मांग की। पीठ ने अपने आदेश के क्रियान्वयन पर एक सप्ताह के लिये रोक लगा दी। राउत को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह मुंबई के बाहरी इलाके तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

सूर्य के पास बढ़ी सौर गतिविधि, भयानक फुटेज साझा किया

नईदिल्ली। आदित्य एल1 ने हाल ही में पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा है और सूर्य की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। धरती की कक्षा को छोड़ने के साथ ही उसके लिए बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। सौर तूफान

उच्च आवृत्ति के साथ पृथ्वी के बाएँ, दाएँ और केंद्र से टकरा रहे हैं। लेकिन केवल पृथ्वी ही ऐसे प्रभावों से नहीं जूझ रही है। हाल ही में नासा ने तीव्र कोरोनल मास इजेक्शन बादल के माध्यम से उड़ान भरने वाले पार्कर सोलर प्रोब का भयानक फुटेज साझा किया। यह पहली बार था जब नासा के अंतरिक्ष यान को इस तरह की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा और वह इस घटना से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा और रास्ते में कुछ महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया। हालाँकि, इस तरह के प्रभावों से उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को समान रूप से बुरी तरह से नुकसान पहुंचने के लिए जाना जाता है और इसरो के आदित्य -11 मिशन अंतरिक्ष यान के सूर्य का निरीक्षण करने के लिए चार महीने में लगांगे 1 बिंदु पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के साथ यह डर है कि इसे भी इसी तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है।

महिला आरक्षण में अतीत के रोड़े और भविष्य की अड़चन

स्वाति

नये सदन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को नारीशक्ति वंदन विधेयक नाम से पेश कर सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। बयानबाजी का मौसम पूरे परवान पर है और अब संसद में प्रस्तावित सात घंटे की बहस यह प्रमाणित करेगी कि आखिरकार सही मायने में कौन इसके पूर्ण समर्थन में हैं, कौन सशर्त समर्थन में हैं और कौन विरोध में हैं।

मोदीजी ने यह विधेयक लाकर इंडी एलायंस की एकता की भी परीक्षा ली है। यह स्वतन्त्र रूप से कांग्रेस की भी परीक्षा की घड़ी है कि वह घटक दलों की सहमति कैसे बनाती है और जनगणना और परिसीमन के बाद इसके लागू किये जाने का स्वागत करती है या विधेयक से अपनी सहमति का पल्ला झाड़ लेती है। राज्यसभा में खड़गे के बयान के भी अपने मायने हैं जिसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग के आरक्षण की बात कही। विधेयक से कन्नी काटने की नज़र से भी इसे देखा जा सकता है।

महिलाओं ने दोनों सदनो में अपने उचित प्रतिनिधित्व के लिए बहुत प्रतीक्षा की है। लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद भी यह आरक्षण उच्च सदन और विधान परिषदों में लागू नहीं होगा तो एक अधूरेपन का एहसास तो हो ही रहा है। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इस विधेयक ने बहुत प्रतीक्षा की है। बस अबकी प्रतीक्षा को परिणति में बदलने की प्रबल संभावना दिख रही है।

इतिहास पर नज़र डाले तो सबसे पहले इस

विधेयक को सितंबर 1996 में 13 पार्टियों के गठबन्धन वाली एच डी देवगौडा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार लेकर आई थी। इनके आपसी मतभेद ने ही विधेयक को आगे बढ़ने से रोक दिया। विरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से इसे सीपीआई की गीता मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति ने 7 बदलाव की मांग रखी जो मंज़ूर नहीं की गई और विधेयक अधर में लटक गया। इसी समय नीतीश कुमार ने इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग रखी थी और इसी आधार पर विधेयक का विरोध किया था। 16 मई 1997 को इसी सरकार ने दोबारा प्रयास किया पर इस बार सरकार के भीतर से ही विरोध की आवाज़ उठी और विधेयक एक बार फिर औंधे मुँह गिर गया।

1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने भी इस विधेयक को पास कराने का भरपूर प्रयास किया था पर हर बार असफल रहे। 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में इस विधेयक की तो बात करते ही कोहराम मच गया था। राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने स्पीकर के हाथ से लेकर इस बिल को फाड़ दिया था। हास्यास्पद यह रहा कि कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए उन्हें सपने में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। इसलिए उस समय यह विधेयक पेश भी नहीं किया जा सका था।

11 दिसंबर 1998 को इस विधेयक पर संसद में फिर हंगामा मचा। उस समय ममता बनर्जी ने विरोध जता रहे सपा के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़ लिया था। अटल जी की सरकार ने एक बार पुन: इसे 23 दिसंबर 1998 को पेश किया। सपा, बसपा, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के विरोध के बाद भी इसे लाया गया पर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा। दिसंबर 1999 को सरकार के पुनर्गठन के बाद फिर प्रयास किया गया पर असफलता ही हाथ लगी। 2000, 2002 और 2003 में लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद इस विधेयक को एनडीए पास नहीं करा पाई।

2008 में यूपीए की सरकार ने पुन: प्रयास प्रारंभ किया और आखिरकार 2010 में इसे राज्यसभा में पारित करा लिया पर लोकसभा में यह बिल पेश भी नहीं किया जा सका था। एनडीए के 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों में ऐसे विधेयक की बात की जाती रही है। आखिरकार इसे 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है। नया विधेयक कुछ मामलों में पहले पेश किए गए विधेयकों से अलग है। इस संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 में तीन नए अनुच्छेद और एक नया खंड शामिल किया गया है।लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक के अनुसार लोकसभा की अनारक्षित सीटों पर एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।

विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रही प्रदेश की आधी आबादी : मुख्यमंत्री बघेल

दुर्ग भिलाई। दुर्ग में गुरुवार को महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं के सम्मान को लेकर कई बातें कहीं। साथ ही सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में आज के समय में महिलाएं आगे हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सबसे आगे हैं। चाहे घर का काम हो या ऑफिस का काम। सभी जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हमेशा से ही बराबरी का स्थान मिला है। महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं और घर के काम भी कर रही हैं। साथ ही परिवार का ख्याल भी रख रही हैं। छत्तीसगढ़ में परिवार और समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा रहा है। लैंगिक अनुपात में भी छत्तीसगढ़ आगे है।

सीएम बघेल ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति हर कलेक्ट्रेट में लगाई जा रही है। अब भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति रथ की सीढ़ियों में लगाकर अपमान कर रही है। छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थलों को सजाने-संवारने का काम हमारी सरकार की ओर से किया जा रहा है। हम महिलाओं को संपन्न और सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन केंद्र, एतिहासिक

धरोहर को सजाने-संवारने और संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ महतारी योजना की घोषणा हमने की है।

साथ ही सीएम बघेल ने दावा किया कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रुप से किसानों को मजबूत करने का काम किया है। प्रियंका जी ने स्टॉल में देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। बीपीओ खोले गए हैं। गारमेंट फैक्ट्री खोली गई है। कैसे आर्थिक संपन्नता आए, इस बात का प्रयास हम करते हैं। राशन कार्ड हमने दिया। हाफ बिजली बिल योजना लाई। पहले भिलाई में बिजली नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहां भी बिजली मिल रही है। भिलाई की पहचान स्टील प्लांट से है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरु की देन है। यहां पहली बार सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में आईं थीं।

सीएम बघेल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि, केन्द्र की मोदी सरकार लूटने का काम कर रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल है। सभी को लगना चाहिए कि यह हमारी सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि गरीबों, किसानों का कैसे विकास हो। भाजपा वाले गौठान में गाय नहीं बल्कि वोट खोजने गए थे। गोधन न्याय योजना के तहत 265 करोड़ का हमने गोबर खरीदा, लेकिन 1300 करोड़ का घोटाला करने का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है।

सीएम बघेल ने कहा कि, केंद्र सरकार सिर्फ अड़ंगा डालने का काम करती है। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं, मितानिनों का मानदेय बढ़ाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। डीए बढ़ाया है। स्वसहायता समूह का कर्ज माफ किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम 3 फीसदी ब्याज पर कर्ज दे रहे हैं। कन्या विवाह योजना के तहत हम 50 हजार रुपए दे रहे हैं। हमारी सरकार 35 किलो चावल दे रही है। तीज-त्यौहार के लिए छुट्टी दी जा रही है।बता दें कि अपने संबोधन के दौरान सीएम बघेल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही बीजेपी पर छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान का आरोप लगाया। सीएम ने दावा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आर्थिक रुप से मजबूत हैं।

महिला आरक्षण बिल पर अंबिकापुर में पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं

सरगुजा। चुनाव में महिला आरक्षण बिल का सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने यह बिल पेश किया है। जिस पर सरगुजा में धार्मिक, सामाजिक संगठन सहित विपक्षी दल के नेता ने भी इस बिल का स्वागत किया है। सभी ने इसे महिला सशक्तिकरण के लिये बेहतर बताया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने बिल का स्वागत करते हुये इसका श्रेय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिया है।

टीएस सिंहदेव ने कहा कि महिला आरक्षण पर जोर देते हुए सबसे ज्यादा सोनिया गांधी को देखा। सोनिया गांधी लगातार ये कहती रही कि महिला आरक्षण होना चहिए। यूपीए की सरकार में लोकसभा से ये बिल पास भी हो गया था और राज्य सभा में पेंडिंग था। अब इस सरकार ने जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है इसका स्वागत है। टीएस सिंहदेव ने कहा इसके लिये सोनिया जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद की, उन्होने सोनिया जी की बात को सुना।

बजरंग दल के संयोजक विकास शर्मा कहते हैं ये बहुत ही सकारात्मक और अच्छी पहल है। पिछले कुछ सालों से अलग अलग

सरकारों ने इस बिल को लाने की कोशिश की। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि वर्तमान सरकार में जो इस बिल को लाने का प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। इससे महिला सशक्तीकरण की बात को सार्थक बल मिलेगा। हमारे देश मे आधी जनसंख्या महिलाओं की है, अब महिला सशक्तिकरण बातों में ही नहीं धरातल पर भी दिखेगा।

विश्व हिंदू परिषद के जिले के प्रमुख विनीत गुप्ता कहते हैं कि ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। हमारे देश मे महिलाओं की बराबरी की बात कही जाती है और लोकसभा में अगर 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल आ जाता है तो उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी होगी दुनिया के सामने महिलाओं का वर्चस्व दिखेगा।

11 वां वेतन समझौता अब डीपीई के पाले में, 27 को चेयरमैन ने बुलाई बैठक

कोरबा। कोयला कामगारों को 11 वां वेतन समझौता पर आए उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कोयला मंत्रालय ने प्रस्ताव डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ;डीपीईद्ध को भेज दिया। इसेक साथ ही हड़ताल को टालने के लिए कोल इंडिया ने पहल शुरू कर दी और चेयरमैन ने श्रमिक संघ प्रतिनिधियों की 27 सितंबर को बैठक बुलाई है।

जुलाई 2021 से लंबित कोयला कामगारों का 11 वां वेतन समझौता पर 20 मई 2023 को जेबीसीसीआइ की बैठक में सहमति बनी और इसके बाद जून माह में मिलने वाला वेतन बढ़े हुए दर पर भुगतान किया गया। वहीं 23 माह का लंबित एरियर का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ माह सितंबर में एकमुश्त प्रदान किया गया। कर्मचारी अभी इसकी खुशी ठीक से मना नहीं पाए थे कि अधिकारियों ने वेतन समझौता को डीपीई गाइड लाइन का उल्लंघन बताया और अधिकारियों से अधिक वेतन होने का विरोध जताते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश बिलासपुर छत्तीसगढ़ व दिल्ली में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद वेतन समझौता को रद्द कर डीपीई को भेजने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही 60 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वेतन समझौता का मामला अटकता दिखाई पड़ने लगा है।

श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने बैठक कर अधिकारियों की कार्यप्रणाली की न केवल निंदा की, बल्कि तीन दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दे दी है। इधर कोयला मंत्रालय के अवर सचिव अरविंद कुमार ने डीपीई के सचिव व निदेशक को

पत्र लिख कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दायर मामले का संदर्भ लेने कहा है। साथ ही कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हाल ही में लागू एनसीडब्ल्यू.11 डीपीई के 24 नवंबर, 2017 के दिशानिर्देश के खंड चार और पांच का उल्लंघन है। कामगारों का वेतनमान अफसरों से अधिक नहीं हो सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, इसके कारण मंत्रालय द्वारा एनसीडब्ल्यू.11 की पुष्टि की गई है।

उच्च न्यायालय ने कोयला मंत्रालय की 22 जनवरी, 2023 की मंजूरी रद्द कर दी गई है। इसलिए उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय लेने के लिए मामला डीपीई को भेजा गया है। इसके साथ ही अब गेंद डीपीई के पाले में पहुंच गई है। चूंकि 60 दिन के भीतर निर्णय लेना है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बैठक कर डीपीई इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेगा। एचएमएस के महामंत्री व जेबीसीसीआइ सदस्य नाथूलाल पांडेय ने बताया कि वेतन में कटौती होने पर कोयला उद्योग में तीन दिवसीय हड़ताल होना तय है।

चार दिन से जारी बारिश ने खेतों को दी संजीवनी

जशपुर। बीते चार दिनों से जशपुर जिले में जारी बारिश ने किसानों की सूख रही फसल के लिए संजीवनी का काम कर दिया है। कृषि विभाग ने उड़द की फसल में यदि फल लग गए हैं तो उसमें कीड़े लगने की संभावना जताई है। शेष सभी फसलें धान, मक्का, मूंगफली, रागी, सब्जी की फसलों को बारिश से फायदा मिल रहा है।

सेन्द्रिमुंडा, जोकारी, केराडीह, गिनाबहार के किसानों ने बताया कि इस बार कम बारिश की वजह से हमारी फसल खतरे में आ गई थी। सोमवार से रोज अच्छी बारिश होने से खासकर धान की फसल को जीवनदान मिला है। इससे पहले धान के खेतों में कम बारिश की वजह से घास काफी बढ़ रही थी। वहीं, धान की पत्तियां भी पीली पड़ने लगी थी। धान की बाली अभी फूटी नहीं है, जिसके कारण बारिश की बेरुखी से किसान खासे चिंतित थे।

कृषि विभाग के एसडीओ कमलेश पैंकरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा धान की अच्छी कीमत देने के कारण

किसान धान को आय का मुख्य साधन बनाकर खूब खेती कर रहे हैं। इस बार जशपुर जिले में औसत बारिश कम रही है। पिछले चार दिनों से पूरे जशपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे धान के खेतों में पानी जमा हो गया है। इसके साथ ही इस बारिश से अन्य फसलें भी अच्छी होंगी। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीयन का कार्य सहकारी समिति व कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023तक है। इस वर्ष धान खरीदी का समर्थन मूल्य 2,183 रुपये है तथा राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ 9,000 रुपये दिया जायेगा। साथ ही दलहन तिलहन रागी कोदो कुटकी एवं मक्का फसल के पंजीकृत किसानों को भी प्रति एकड़ 9,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

बड़े नक्सलियों की बस्तर में मौजूदगी किसी बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम

जगदलपुर। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने पार्टी का 19वां स्थापना दिवस 21 सितंबर से मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। मिली जानकारी के अनुसार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बड़े नक्सलियों के पिछले दो माह से बस्तर में उनकी मौजूदगी की खबर एवं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के सरहदी इलाकों में नए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। जिसके चलते सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिये गये है। वहीं कोंटा-भद्राचलम मार्ग पर रात्री 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एतिहातन आवगमन बंद कर दिया गया है तथा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 80 लाख रुपये के इनामी नक्सली संजय दीपक राव को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा क्षेत्र अंतर्गत तेलंगाना इलाके में नक्सली गतिविधियां सक्रिय हैं। नक्सली अपने बड़े लीडर के पकड़े जाने पर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं।

नक्सलियों के 19 वां स्थापना दिवस 21 सितंबर से एक दिन पहले 20 सितंबर को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिला नक्सलियों 5 लाख की ईनामी मलांगिर एरिया कमेटी सदस्या/एरिया मिलिशिया कमाण्ड इन चीफ कुमारी लक्खे उर्फ जिलो माड़वी एवं 2 लाख की इनामी प्लाटून 24 सदस्य नक्सली मंगली पदामी को ढेर कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था, इस दौरान 40 लाख के ईनामी नक्सली कमांडर चैतू समेत अन्य

नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलियों के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण सब जोनल इलाके में एक वर्ष के अंदर कामरेड दूला दादा, केंद्रीय पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड बसंत की बीमारी से हुई अचानक मौत को अपने आंदोलन का बड़ा नुकसान बताया है। यह भी बताया गया है कि तेलंगाना में केंद्रीय कमेटी के एक नक्सली नेता को गिरफ्तार किया गया है। इसके चलते नक्सलियों में जबरदस्त आक्रोश है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। इधर जगदलपुर रेलवे स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सली सप्ताह के चलते रेलों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है। यात्री और मालगाडियां निर्बाध गति से दौड़ रही हैं। स्टेशन मास्टर ने बताया कि नक्सली बंद के चलते रेल परिवहन रोकने के लिए किसी भी प्रकार का पत्र मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। बस्तर आईजी सुन्दरराज पी. ने कहा कि नक्सली सप्ताह से एक दिन पूर्व नक्सलियों के मलांगिर एरिया कमेटी सदस्या के मारे जाने से नक्सलियों को भारी क्षति हुई है। आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में नियमित रूप से अभियान जारी रहेगा, ताकि नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एमसीबी में 3 महीने में टूट गई 3 करोड़ की नहर

एमसीबी। मार्च महीने में जनकपुर के पचनी डैम में नहर का निर्माण व रिपेयरिंग काम किया गया। इसमें 3 करोड़ 75 लाख की लागत आई। लेकिन बारिश शुरू होते ही नहर का करीब 40 मीटर हिस्सा ढह गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जल संसाधन विभाग से की। जनकपुर क्षेत्र के आसपास के 10 गांव के किसानों को खेती के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराने मार्च के महीने में 7 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई। इस नहर को 250 एकड़ खरीफ व रबी की फसल की सिंचाई के लिए बनाया गया था। लेकिन बारिश शुरू होते ही नहर का 40 मीटर हिस्सा ढह गया। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अफसर और ठेकेदार पर मिलीभगत कर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर का काम 3 महीने पहले की पूरा हुआ था। उप सरपंच अरिमरदन सिंह ने कहा ठेकेदार और अफसर ने मिलीभगत कर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया है। विरोध के बाद भी ठेकेदार ने मनमाने ढंग से नहर का निर्माण किया।

दुर्ग नौतनवा का स्टापेज होगा सलेमपुर, रंग लाया संघर्ष

भिलाई। छत्तीसगढ़ यूपी बिहार रेल यात्री सेवा संघ की दशकों पुरानी मांग रेल मंत्रालय ने मान ली है और लंबे संघर्ष के बाद दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को सलेमपुर स्टॉपेज दिया गया है। अपनी इस मांग को लेकर संघ की ओर से पोस्टकार्ड से लेकर ज्ञापन सौंपने तक कई अभियान दुर्ग-भिलाई और उत्तर प्रदेश में चलाए गए। इसके बाद अब रेलवे प्रशासन ने इस आशय की सूचना जारी कर दी है। संघ की ओर से अध्यक्ष हाजी एमएच सिद्दीकी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय से लेकर सलेमपुर के सांसद रविन्द्र कुशवाहा तक ज्ञापन दिए गए वहीं जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन को भी ज्ञापन भेजे गए थे। अंतत: यह मांग पूरी हुई। उन्होंने बताया कि सलेमपुर ऐसा जंक्शन है जहां से कई क्षेत्रों में लोग अपने-अपने साधनों से जा सकते हैं। वहां से बिहार के सीवान, गोपालगंज और मैरवा सड़क मार्ग से जुड़ा है। यूपी के पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में सड़क मार्ग से जाया जा सकता है।

अभिषेक बंजारे सिहावा विस के सोशल मीडिया अध्यक्ष बने

नगरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री

दीपक बैज जी व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल एवं सोशल मीडिया श्री जयवर्धन बिस्सा जी की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने हेतु श्री नमन झाबक जैन लोकसभा अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल एवं सोशल मीडिया के निर्देशानुसार सिहावा विधानसभा प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल एवं सोशल मीडिया के अध्यक्ष अभिषेक बंजारे बनाए गए। श्री बंजारे बैंगलूर स्तिथ यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निरंतर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए कार्य कर रहे है । उनकी सोशल मीडिया में गतिविधियों को देखते हुए काँग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है। सिहावा विधानसभा आईटी सेल एवं सोशल मीडिया में उपाध्यक्ष राहुल देवांगन, सतीश जांगड़े ,महासचिव नरेश कुमार , सचिव मनीष कुंजाम, सदसय सुनील साहू ,फैजल खान, सूर्यकांत पटेल, साहिल साहू, विवेक साहू आदि को पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

परिवर्तन यात्रा का आज भव्य स्वागत होगा : खिलेश्वरी

धमतरी। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 22 को धमतरी पहुँच रही है । परिवर्तन यात्रा की तैयारी हेतु वृहत स्तर पर तैयारी चल रही है । पार्टी संगठन प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहा है । व्यवस्था मे लगे कार्यकर्ता अपने स्तर पर साज सज्जा एवं अतिथियों तथा कार्यकर्ताओं को बेहतर व्यवस्था मिल सके इसकी चिंता मे लगे हैं । बुधवार को ग्राम देमार मे आसपास के 10 गाँव के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेने जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, महामंत्री कविन्द्र जैन, विधानसभा संयोजक अरविंदर मुंडी पहुंचे । देमार मे स्वागत कार्यक्रम की प्रभारी श्रीमती खिलेश्वरी किरण एवं मुरारी यदु ने बैठक मे तैयारियों के विषय मे बताया कि आतिशबाजी, पुष्प वर्षा एवं बाजे गाजे के साथ परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया जायेगा। जिलाध्यक्ष शशि पवार सहित जिला एवं मण्डल की सक्रियता से कार्यकर्ताओं मे इस कार्यक्रम को लेकर खासा जोश देखा जा रहा है। यात्रा के मार्ग को झंडों और होर्डिंग्स से सजाया जा रहा है।

किसान ने लॉटरी के चक्कर में गंवाए 18 लाख

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। दामापुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत 25 लाख रुपए की लाटरी के चक्कर में किसान से 18 लाख रुपए की ठगी हुई है। यह किसान बीते नौ महीने से लॉटरी के रुपए लेने के लालच में 40 किस्तों में रुपए भेजता रहा। जब राशि नहीं मिली तो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी अनुसार, दामापुर चौकी क्षेत्र के तुलसीखैरा गांव का किसान शत्रुहन कुमार के मोबाइल पर 25 लाख रुपए की लॉटरी निकलने का मैसेज आया था। इनाम के रुपए की लालच में जब उसने मैसेज का रिप्लाई किया, तो उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। जिसके बाद उसे 25 लाख की लॉटरी का झांसा दिया गया। फिर लॉटरी के 25 लाख रुपए देने के एवज में प्रोसेसिंग फीस की मांग की गई। लालच में पड़कर पीड़ित किसान ने पैसे ट्रांसफर करता रहा। इस तरह पिछले नौ महीने तक किसान 40 किस्तों में पैसा भेजता रहा। उसने जमीन बेचकर मिले 18 लाख रुपए जालसाजों के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की नियत साफ नहीं : लक्ष्मी

नगरी। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया है। इस पर सवाल उठाते हुए सिहावा विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी सरकार की नियत साफ नहीं है। देश की आधी आबादी को साधने के नाम पर उनके साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार महिलाओं की वाकई हितैषी होती तो महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जाता, लेकिन सरकार में जानबूझकर विधेयक में ऐसा प्रावधान किया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले महिला आरक्षण लागू होना संभव नहीं है जिसके कारण इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।

वहीं आगामी समय में विभिन्न प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यह विधेयक महिलाओं के लिए किसी काम का नहीं रहेगा। मोदी सरकार की कोशिश सिर्फ और सिर्फराजनीतिक लाभ लेने की नजर आती है। विधेयक में सम्बन्ध में बताया कि इसमे किये गए प्रावधान के मुताबिक जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। 2021 में जनगणना होने वाली थी जो अब तक नहीं हुई है।

वहीं महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद भी तब होगा जब परिसीमन किया जाएगा। मतलब महिला आरक्षण के लागू होने की राह में अब भी दो रोड़े हैं पहला जनगणना और दूसरा परिसीमन। इससे संकेत मिलता है कि महिला आरक्षण का प्रावधान 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही लागू हो पाएगा। विधेयक में कहा गया है कि आरक्षण शुरू होने के 15 साल बाद प्रावधान प्रभावी होना बंद हो जाएंगे। इस बात पर ऐतराज है कि आखिर महिला आरक्षण के लिए 15 वर्ष की अवधि ही क्यों सीमित रखी गई है। नारी शक्ति वंदन विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पर इसमे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला-बदली होगी। यह महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने प्रावधान नजर आता है। डॉक्टर ध्रुव ने आगे कहा कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना कभी भी मोदी सरकार नहीं चाहती है, इसलिए आरक्षण के नाम पर सिर्फ झुनझुना थमाया गया है। कांग्रेस के द्वारा पिछले 9 साल से महिला आरक्षण विधेयक की मांग की जा रही थी लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव के समय आधी-अधूरी तैयारी के बीच यह विधेयक लाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है। आरक्षण को लेकर भाजपा की हमेशा दोहरी नीति रही है, एक ओर छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार के द्वारा दिये जाने वाले आरक्षण को राज्यपाल के द्वारा अटकाकर रखा गया दूसरी ओर महिला आरक्षण विधेयक लाकर महिलाओं का हितैषी बनने का सिर्फ ढोंग किया जा रहा है।

हजारों शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा पुरानी पेंशन का लाभ

कबीरधाम। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन इसके नियम के चक्कर में कई शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा। इसी समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कवर्धा विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर से स्थानीय सर्किट हाउस में मुलाकात कर शिक्षक संवर्ग के चार सूत्रीय मांगों पर चर्चा की। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्रवंशी ने बताया कि पुरानी पेंशन व क्रमोन्नति की मांग जनघोषणा पत्र 2018 में शामिल है, जिसमें पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया गया है। लेकिन शिक्षक एलबी संवर्ग को संविलियन तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ देने के कारण हजारों शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हो जाएंगे। क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षक एलबी संवर्ग के संविलियन के पहले की सेवा अर्थात शिक्षाकर्मी के पद पर प्रथम नियुक्ति

तिथि से सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन व क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करना, पेंशन निर्धारण के लिए अर्हकारी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र सरकार की तरह 20 वर्ष करना, शिक्षक एलबी संवर्ग को शिक्षक, व्याख्याता व प्राचार्य के रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने की मांग की गई। मंत्री अकबर ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इस विषय पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए महिला आरक्षण : भूपेश

रायपुर। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान दिया है। महिला आरक्षण बिल के मुददे पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए धोखेबाज कहा है। मीडिया से बातचीत में कहा, वे धोखेबाज हैं। जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा। इसमें कई साल लगेंगे। श्रमती सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन हमें ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसे 2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की संगीता ने दक्षिण कोरिया में फहराया देश का झंडा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी संगीता राजगोपालन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ राज्य का बल्कि देश का नाम रोशन करते हुए देश का झंडा फहराया। जिओन्जू (दक्षिण कोरिया) में 11 से 17 सितम्बर तक हुई 13वीं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में संगीता ने पदक की दस्तक तभी दे दी थी, जब उन्होंने द्वितीय चक्र में इंग्लैंड की बैट्टी ब्लेयर को तीन सेटों के मुकाबले में परास्त किया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने नीदरलैंड की एलिजा कून को सीधे सेटों में हराया। सेमीफाइनल में वे जापान की कुशियामा से परास्त हो गई लेकिन देश के लिए पदक पक्का कर दिया। राज्य के बैडमिंटन खिलाड़ियों में संगीता की इस उपलब्धि पर हर्ष जताया है।

शहर में कारोबारी के घर आईटी का दबिश

रायपुर। आयकर विभाग ने लक्ष्मी कृपा स्टील के संचालक राकेश अग्रवाल के स्वर्णभूमि स्थित निवास समेत फैक्ट्री और कुछ अन्य ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि इनके कुछ पार्टनरों के यहां भी छत्तीसगढ़ व ओडीसा में टीम पहुंची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई जारी है,लेकिन विभागीय तौर पर कोई अधिकृत पुष्टि नहीं की हैं।

दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन

रायपुर। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव के द्वारा जारी आदेशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के नियम 34(2) के अधीन राज्य में ऐसे दिव्यांग जो अधिक सहारे की आवश्यकता वाले हों, ऐसे विशेष प्रकरणों की प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रकरण का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना होगा। निर्धारण बोर्ड में कलेक्टर या प्रतिनिधि (अतिरिक्त/संयुक्त कलेक्टर से अन्यून) को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/उपसंचालक को सदस्य/सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक को सदस्य नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की

महिला समृद्धि सम्मेलन, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन केंद्र को संवारने मुख्यमंत्री की बड़ी पहल

भिलाई। जयंती स्टेडियम भिलाई नगर में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चाहे मॉडल जैतखाम बनाने का काम हो, कृष्ण कुंज बनाने का काम हो। वनगमन परिपथ बनाने का काम हो। हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन केंद्र को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा मैं करता हूँ। हम हर तीन महीने में किसानों को पैसा दे रहे हैं। भूमिहीन श्रमिकों को पैसा दे रहे हैं। बटन दबाते हैं और पैसा किसानों के पास पहुँच जाता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई की पहचान स्टील प्लांट से हैं, इसे नेहरू जी ने बसाया था। मातृशक्ति को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सबसे आगे हैं। चाहे घर का काम हो या ऑफिस का सभी जगह महिलाएं आगे आकर काम कर रही हैं। शुरू से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हमेशा बराबरी का स्थान मिला है। महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं और घर के काम भी। छत्तीसगढ़ में परिवार और समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा रहा है। लैंगिक अनुपात में भी छत्तीसगढ़ आगे है। महिलाएं बच्चों के देख-रेख से लेकर पढ़ाई-लिखाई तक ,घर में काम करना, नौकरी भी करती हैं तो सबके लिए खाना बनाकर जातीं है और काम से लौटकर फिर सभी के भोजन का ध्यान रखती हैं। पुरुष और महिलाओं के सहकार से हमारे यहां काम होता है। शुरू से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बराबरी का स्थान मिला है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने का काम किया। अभी प्रियंका जी ने स्टाल में देखा कि किस तरह से काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बीपीओ खोले हैं। गारमेंट फैक्ट्री खोले हैं। कैसे आर्थिक संपन्नता आये, इस बात का प्रयास हम करते हैं। राशन कार्ड हमने दिया। हाफ बिजली बिल आया। पहले भिलाई में नहीं मिल रहा था अब यहां भी मिल रहा है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि उनकी सरकार है। कोरोना काल में भी हमने प्रयास किया कि कैसे लोगों को आर्थिक मंदी से बचाएं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सारी मितानिन बैठी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी हैं। पांच साल में मानदेय पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया। आज हमारी मितानिन बहन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आये हैं। वे बहुत खुश हैं।

भूपेश बघेल ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। डीए हमने बढ़ाया। स्वसहायता समूहों का कर्ज हमने माफ किया। बहनों को सशक्त करने हम लोगों ने महिला समूहों के कर्ज राशि की सीमा बढ़ा दी। हम तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। वे सक्षम बनें और स्वावलंबी बने, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। कन्या विवाह की राशि बढ़ा दी है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सेवा से पृथक होंगी तो उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। हमने हरेली की छुट्टी दी, तीजा की छुट्टी दी। हमने मुख्यमंत्री निवास में तीजा मनाया। मुझे लगता है कि आपमें से बहुत से लोग अभी मायके से लौटी होंगी। बोरे बासी को सम्मान देने का जो काम किया, वो हमने किया। हमारे खानपान की परंपराओं का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कलेक्ट्रेट में लगाई। राजगीत को अपनाया।

अपने संबोधन के बीच मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब प्रियंका दीदी ने भंवरा खेला तो मुझे लगा वे ठीक तरह से नहीं चला पाएंगी लेकिन उन्होंने बहुत बढिया तरीके से भंवरा चलाया, मैं खुद हैरान रह गया। इस बात को सुनकर श्रीमती प्रियंका गांधी भी स्वयं को हंसने से न रोक पाई।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं को प्रियंका ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया

जयंती स्टेडियम भिलाई नगर के महिला समृद्धि सम्मेलन में श्रीमती प्रियंका गांधी को अपने पास पाकर महिलाएं खुश और उत्साहित दिख रही हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने श्रीमती गांधी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर उत्साही महिलाएं श्रीमती गांधी के साथ सेल्फी ले रही हैं। महिला समृद्धि सम्मेलन में अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण बन गया है।महिलाएं अपना काम श्रीमती गांधी को दिखा रही हैं। वे स्टाल्स का अवलोकन कर रही हैं और एक जगह उन्होंने अमारी फूल के रस के बारे में जानकारी ली। महिलाओं ने उन्हें संक्षेप में बताया कि इसका वे किस तरह उपयोग करती हैं।

जब प्रियंका गांधी ने किया सुवा नाच

जयंती स्टेडियम भिलाई नगर में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंची प्रियंका गांधी ने जब किया सुवा नाच। श्रीमती गांधी ने जब यह नृत्य देखा तो वे भी सुवा नर्तकों के साथ समूह में शामिल हो गईं और साथ ही थिरकने लगीं। छत्तीसगढ़ में सुवा नाच बेहद लोकप्रिय है। दीपावली के आसपास सुवा को एक टोकरी में रखकर महिलाएं यह नृत्य करती हैं। इसके माध्यम से वे अपने सुखदुख साझा करती हैं। सुवा गीत के माध्यम से वे अपनी आवाज की भी अभिव्यक्ति करती हैं और अपने समय के समाज के बारे में भी बताती हैं। तोते के जैसे हरे वस्त्रों में समूह में किया गया यह नृत्य बेहद आकर्षक होता है।

भाजपा को झंडा उठाने के लिए कोई नहीं मिल रहा तो परिवर्तन कैसे होगा: कवासी लखमा

सरगुजा। मंत्री कवासी लखमा सड़क मार्ग से सरगुजा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों के सवालों के जवाब में लखमा भाजपा पर हमलावर रहे। शराबबंदी पर यू टर्न लेते हुए इसके सामाजिक दुष्परिणामों का हवाला उन्होंने दिया। जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा को झंडा उठाने वाला भी नहीं मिल रहा है, तो परिवर्तन कैसे होगा।

उन्होंने कहा एमपी में सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी हुई है और प्रदर्शन रैलियां हो रही है। भाजपा ने भी बस्तर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन जिसे झंडा दिखाने आना था, वो पहुंचे ही नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दंतेवाड़ा ही पहुंची और जगदलपुर नहीं गई। क्योंकि वहां भीड़ ही नहीं थी। कांकेर में मैं स्वयं एक बीजेपी के कार्यक्रम में गया था, जहां महज डेढ़ सौ लोग मौजूद थे। भाजपा को झंडा उठाने वाला भी नहीं मिल रहा है, तो परिवर्तन कैसे होगा।

कवासी लखमा ने कहा भाजपा के पास चुनाव लड़ने चेहरा ही नहीं है, जबकि हमारे पास भूपेश बघेल बड़ा चेहरा है। आज भाजपा छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लेकर घूम रही है, जबकि 15 तक उन्हें भूल गए थे। भाजपा को 15 साल तक आदिवासी विश्व दिवस पर छुट्टी, हरियाली तिहार और छत्तीसगढ़ी परम्पराओं की याद क्यों नहीं आई। इन्होने बासी भात क्यों नहीं खाया, क्या ये सब बातें छत्तीसगढ़ की जनता भूल जाएगी।

कवासी लखमा ने आगे कहा, सरकारें आती जाती है, मैंने भी राजनीति में लम्बा समय व्यतीत किया है। लेकिन ऐसा सीएम नहीं देखा जो देवगुड़ी, घोटुल, भूमिहीन किसान को पैसा देता हो। सामाजिक भवन के लिए सभी समाज को पैसा देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज भूपेश बघेल देश के पहले नंबर के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के सीएम दूसरे नंबर पर है। लेकिन भाजपा शाषित राज्यों के सीएम दूर दूर तक सूची में नहीं आते हैं।

घोषणापत्र में किए वादों को लेकर कहा, सभी मुद्दों की समीक्षा जनता करती है। भाजपा ने भी 15 लाख देने का वादा किया था, 15 पैसे भी खाते में नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, पेट्रोल 35 रुपए से बढ़कर 100 रुपए के ऊपर चला गया। 70 सालों तक गैस का एक दाम 400 रुपए था, जो अब 12 सौ रुपए है।

शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा, शराब सामाजिक बुराई है और इसे बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राजनीति से हटकर सभी दलों से आह्वान किया था कि दूसरे राज्यों में जाकर समीक्षा की जाए। हमें कोरोना में दो माह दारु बंद की, तो 12 लोग अवैध दारु पीकर मर गए। छत्तीसगढ़ में जहां भी जाता हूं, लोग शराब दुकान खोलने का आवेदन देते हैं। हमने नई दुकान नहीं खोली है, लेकिन शराबबंदी होने पर बड़े लोग तो दूसरे राज्यों से शराब ले आएंगे। लेकिन यहां के आदिवासी और गरीबों को जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में 400 आदिवासी जेल में है। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी, जिसमें गरीब को जेल जाना पड़े और नकली शराब पीकर जान गवानी पड़े। गुजरात तो घर पहुंच सेवा दे रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर सरोज पांडे का कांग्रेस पर हमला

रायपुर/दिल्ली। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सरोज पांडे ने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का हैं।

सरोज पांडे ने राज्यसभा में कहा कि साल 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद निर्मला सीतारमण के पास रक्षा मंत्रालय था। अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय था। राजनाथ सिंह के पास गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं और रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर भरोसा किया।

सरोज पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि हर जगह राजनीति हो। कोई भी काम प्रक्रिया के तहत ही होता है। पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया के तहत ही काम होने पर ही प्रावधान के तहत महिलाओं को इसका फायदा मिल सकेगा।

सरोज पांडे ने कहा कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई। जिन राज्यों में बेटी पैदा करना अभिशाप माना जाता था। बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा करने वाली मां भी तनाव में रहती थी। बेटी पैदा होने के बाद बच्ची को दूध के बड़े ओहदे में डाल दी जाती थी, जहां वह अंतिम सांसे लेती थी। देश में जब लिंगानुपात होने लगा तो देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूची में भारत 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया है।

कवर्धा में जिला महामंत्री समेत 16 भाजपाई कांग्रेस में शामिल

कवर्धा। पंडरिया और कवर्धा विधानसभा में बीते दिनों बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची थी। बीजेपी ने आमसभा कर जनता को रिझाने की कोशिश की। रमन सिंह ने तो भूपेश सरकार को भ्रष्टाचारी और घोटाले की सरकार बता दिया। साथ ही अपने 15 साल के भाजपा शासन में हुए विकास का बखान किया। लेकिन भाजपा की यह तरकीब कवर्धा में उल्टी पड़ गई है। भाजपा के ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

बुधवार को कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री मोहम्मद अकबर ने दो ग्राम पंचायत में स्कूल भवन, सामुदायिक भवन और कई ग्रामों में सीसी रोड निर्माण के लिए कुल 12 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया। कवर्धा के सर्किट हाऊस में 33 परिवार को रहवासी पट्टा और 100 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के सामने भाजपा महिला मोर्चा कवर्धा की जिला महामंत्री तमन्ना मेहरा समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 16 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी नए सदस्यों का तिरंगा गमक्षा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मोहम्मद अकबर ने कहा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है। उसका बड़ा उदहारण है दंतेवाड़ा। जहां परिवर्तन का शुभारंभ करने गृहमंत्री अमित शाह आ रहे थे। लेकिन भीड़ नहीं होने के कारण दौरा रद्द कर दिया।

रमन सिंह द्वारा मोहम्मद अकबर को शक्तिशाली बताने वाले बयान पर मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया है। अकबर ने कहा, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास कर रही है। इसलिए लोग दूसरी पार्टी छोड़ बड़ी संख्या में कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं और रमन सिंह का धन्यवाद जो मुझे वे शक्तिशाली व्यक्ति मान रहे। वैसा हम काम भी कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस उद्देश्य से परिवर्तन यात्रा चला रही है कि जनता को वह अपनी ओर आकर्षित कर सके। जिससे विधानसभा चुनाव में अपनी बहुमत लाकर बीजेपी फिर से प्रदेश में सरकार बना सके। इसी कड़ी में 18-19 सितंबर को परिवर्तन यात्रा कवर्धा पहुंची थी। परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। लेकिन इस यात्रा का उल्टा असर देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री मोहम्मद अकबर के कामकाज से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आज: रायगढ। आगामी विधानसभा निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों/वाहनों के मानक दर निर्धारण के संबंध में परामर्श हेतु जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक 22 सितम्बर 2023 को दोपहर 01 बजे से अपर कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 21 में आयोजित की गई है।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH,
WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI GODAWARI BASIN
RAIPUR (C.G.)
e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
CORRIGENDUM No.- I

In System Tender No. 146944 /N.I.T. No.: 28/SAC/2023-24, Balod , Dated: 08.09.2023
Whose G-Number is 05151. dated 11.09.2023, following amendments are made :-

S.No.	Earlier Published	Amendments Now Read as
1	The details can be viewed and downloaded online from Date15.09.2023 at 17.31 Houses (IST) onwards	The details can be viewed and downloaded online from Date 21.09.2023 at 17.31 Houses (IST) onwards
2	Online Tenders are invited for the work up to 25.09.2023 at 17.30 Hours	Online Tenders are invited for the work up to 03.10.2023 at 17.30 Hours
3	Bid Open Start Date and time: 26.09.2023 11:30 Hours	Bid Open Start Date and time: 04.10.2023, 11:30 Hours

Note: All other terms and conditions will be unchanged

Executive Engineer
Water Resources Division,
Balod (C.G.)
For, Chief Engineer, Mahanadi Godavari Basin
Raipur (C.G.)

जी-05530/8

महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद प्रदेश की राजनीति में दिखेगा महिलाओं का दबदबा

रायपुर। लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। बिल के मुताबिक राज्यों की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इसे ऐसे समझते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद 90 में से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यानी 70 सीटों पर ही पुरुष अपनी दावेदारी कर सकेंगे। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें है। आरक्षण बिल लागू होने के बाद 3 लोकसभा सीटें महिलाओं के कब्जे में चली जाएगी। 8 सीटों पर ही पुरुष उम्मीदवार रहेंगे।

वर्तमान में प्रदेश की 90 विधानसभा सीट में 16 सीटों पर महिलाएं काबिज है। इन 16 महिला विधायकों में 13 विधायक कांग्रेस की हैं। भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से एक एक महिला विधायक है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सीट में से 13 सीटें महिलाओं ने जीतीं। इसके बाद प्रदेश में हुए तीन उपचुनाव में कांग्रेस तीन महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और तीनों ने जीत हासिल की। बात करें छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की तो कुल 11 सीटें हैं जिसमें से 3 सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। इन 3 सीटों में से दो भाजपा और एक कांग्रेस के पास है। यदि राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो प्रदेश में कुल 5 राज्यसभा सीटें हैं। जिसमें से वर्तमान में 3 सीटों पर महिला सांसदों का कब्जा है। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और एक पर भाजपा सांसद काबिज है।

निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी 3 करोड़ 3 लाख 80 हजार है। कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 96 लाख 40 हजार 430 मतदाता है, जो आबादी का लगभग 64.65 प्रतिशत है। कुल वोटर्स में पुरुष मतदाताओं की संख्या 98 लाख 6 हजार 906 है, जबकि महिला मतदाता 98 लाख 32 हजार 557 है। थर्ड जेंडर 767 हैं। इन आंकड़ों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। प्रति हजार पुरुष पर 1003 महिला मतदाता हैं।

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस महिला विधायक लक्ष्मी ध्रुव का कहना है कि मनमोहन सरकार के दौरान महिला आरक्षण बिल लाना चाहती थी लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया था। यदि उस दौरान हमारी सरकार रिपीट होती तो अब तक यह बिल पास हो जाता। 9 साल तक भाजपा इस बिल को नहीं लाई और अब चुनाव आ रहा है तो महिलाओं को प्रभावित करने के लिए यह बिल पास किया गया। लेकिन लेकिन इसका लाभ साल 2024 के चुनाव में महिलाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि परिसीमन के बाद ही इसका लाभ महिलाओं को मिल सकता है और साल 2026 के पहले यह संभव नहीं है। लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि उसमें एससी एसटी ओबीसी को कितने प्रतिशत दिया जाएगा वह अभी देखना महत्वपूर्ण होगा।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2. सिरपुर भवन परिसर रायपुर (छ.ग.)
(निविदा संशोधन सूचना)

क्रमांक- 4280 / NIT-19/2023-24/नि.लि. दिनांक 13/09/2023

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:-	29.09.2023 अपरान्ह 5.30 बजे तक
2. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	06.10.2023 अपरान्ह 5.30 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि	:-	09.10.2023 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
5. निविदा प्रपत्र की कीमत प्रत्येक हेतु (रू. में)	:-	रुपये 750.00
6. निविदा प्रपत्र का प्रकार	:-	प्रपत्र "A"
7. निविदाकारों की श्रेणी	:-	द-पंजीयन के अंतर्गत "द" से "अ" श्रेणी तक
8. कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	T0072 & T0073 हेतु 01 माह वर्षा ऋतु सहित। T0074 हेतु 02 माह वर्षा ऋतु सहित ।

एन आई टी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम No of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रू. में) बैंक साल्वेंसी (रू. में)
1	2	3
19 T0072	VARIOUS WORK IN ENGINEERING COLLEGE CAMPUS SEJBAHAR (RHS) FOR ASSEMBLY ELECTION 2023 UNDER SUB DIVISION NO.-4 (ARANG) RAIPUR (प्रथम आमंत्रण)	19.96 15,000.00 3,00,000.00
19 T0073	VARIOUS WORK IN ENGINEERING COLLEGE CAMPUS SEJBAHAR (LHS) FOR ASSEMBLY ELECTION 2023 UNDER SUB DIVISION NO.-4 (ARANG) RAIPUR (प्रथम आमंत्रण)	19.78 15,000.00 3,00,000.00
19 T0074	S/R WORK OF ROAD FROM OLD DHAMTARI ROAD TO ENGINEERING COLLEGE MAIN GATE (LHS & RHS) SEJBAHAR, RAIPUR UNDER SUB DIVISION NO.-4 (ARANG) RAIPUR (प्रथम आमंत्रण)	19.90 15,000.00 3,00,000.00

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. -2
रायपुर (छ.ग.)

जी-05512/6

कनाडा के रवैये से भारत के साथ बिगड़ेंगे संबंध

अनिल त्रिगुणायत

कनाडा पिछले चार दशकों से ज्यादा समय से आतंकवादी और अलगाववादी समूहों को पनाह दे रहा है। इस वजह से आज वे बहुत ताकतवर हो गये हैं और अब राजनीति में भी उनका दबदबा होता जा रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ऐसे समूहों का पूरा कब्जा हो चुका है। वहां अब ऐसे लोग मंत्री भी बन रहे हैं और गुरुद्वारों में भी उनका आधिपत्य हो गया है। ऐसे तत्व अब वहां से खालिस्तान के पृथकतावादी आंदोलन, या किसान आंदोलन जैसे मुद्दों से भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो भी ऐसे तत्वों को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य कमजोर नजर आ रहा है। कनाडा में एसएफजे नाम के एक अलगाववादी संगठन ने पिछले दिनों ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे में खालिस्तान के नाम पर जनमत संग्रह भी आयोजित करवा दिया। यह घटना ऐसे दिन हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, और जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री से वहां जारी भारत-विरोधी घटनाओं के जारी रहने पर गहरी चिंता जतायी थी। ऐसी घटनाओं से भारत के सामने काफी परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि सारी दुनिया में भारत ने आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। भारत कनाडा को लगातार ऐसे गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहा है, मगर वे हमारी जायज चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे। ट्रुडो का पारिवारिक अतीत भी ऐसा ही रहा है। वर्ष 1982 में भारत ने कनाडा से बलविंदर परमार नाम के एक अलगाववादी को सौंपने की मांग की थी, लेकिन तब ट्रुडो के पिता और कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रुडो ने यह कहते हुए सहयोग नहीं किया कि भारत चूंकि राष्ट्रमंडल का हिस्सा है इसलिए यह संभव नहीं है। इसके बाद 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान में बम धमाका हुआ और भारत उसके बारे में भी कनाडा से लगातार आवाज उठाता रहा। फिर, वहां से एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या का महिमामंडन किया गया। अब इसके बाद हरदीप सिंह निज्जर की मौत आपसी गैंगवॉर में हुई, लेकिन कनाडा ने उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है, और हमारे राजनयिकों को निशाना बनाया है। इससे एक बार फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे भारत विरोधी तत्व कनाडा में काफी प्रभावशाली हो चुके हैं। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बीच में थोड़ी कम हो गयी थीं। भारत में भी, और कनाडा में भी खालिस्तान समर्थक गुटों की संख्या बड़ी नहीं है। बब्बर खालसा, सिख फॉर जस्टिस या टाइगर फ्रंट जैसे गुटों को छोड़ दिया जाए, या गुरुद्वारों पर आधिपत्य जमाये लोगों को छोड़ दिया जाए, तो कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोग पूरी तरह से भारत के साथ हैं। लेकिन, खालिस्तान समर्थकों ने एक राजनीतिक प्रभाव कायम कर लिया है, जिसका वे लाभ उठाते हैं, और वहां की सरकार भी इन गुटों के साथ हो गयी है। वहां ऐसे ही लोग मंत्री भी बन रहे हैं। ऐसे लोग जानकर ऐसा प्रचार करने की कोशिश करते हैं जैसे कनाडा के सारे भारतीय समुदाय का समर्थन उनके पास है। जस्टिन ट्रुडो वर्ष 2018 में जब बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली भारत यात्रा पर आये थे तो उस दौरान भी उनके प्रतिनिधिमंडल में एक खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल शामिल था। इससे भी अंदाजा मिलता है कि वह कैसे अपने मेजबान भारत का अपमान कर रहे थे। इसी प्रकार पिछले दिनों जी-20 सम्मेलन के दौरान जब भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, तब भी उनसे कहा गया कि वह भारत विरोधी तत्वों को काबू में करें और राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर तो कुछ नहीं किया लेकिन जाकर संसद के निचले सदन में एलान कर दिया कि उनकी खुफिया एजेंसियां खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने की संभावना की जांच कर रहे हैं। कनाडा के नागरिक निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। लेकिन, ट्रुडो ने यह बयान देते हुए कोई सबूत नहीं दिये, जबकि भारत ने हर बार सबूतों के साथ बात की है। उन्होंने एक कहानी बनायी और स्थानीय लोगों का वोट बटोरने के उद्देश्य से यह कदम उठा डाला। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है और जवाब कार्रवाई करते हुए भारत ने भी उनके एक राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री के बयानों को पूरी तरह खारिज भी कर दिया है।

भाजपा ने सजाई सांगठनिक सेना

उमेश चतुर्वेदी

लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा उसे पसंद करती है, जिसकी नीतियों और लोककल्याणकारी योजनाओं को वह अपने लिए सबसे ज्यादा मुफीद पाती है। लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष है। लोकतंत्र में जीत और हार के कई और भी कारण होते हैं। इसीलिए आज सत्ता के चयन के लिए होने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनावों को आज युद्ध का दर्जा हासिल हो चुका है। युद्ध के लिए जिस तरह सैनिकों के मनोबल की जरूरत होती है, अच्छी रणनीति चाहिए होती है, कुछ इसी अंदाज में आज राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की कोशिश करते हैं और अपनी रणनीति बनाने में मशगूल रहते हैं। चुनावों में चूंकि संगठन की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए हर दल चाहता है कि उसका जमीनी स्तर तक संगठन मजबूत रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कुछ दिन पहले ही अपने करीब 71 प्रतिशत जिलाध्यक्षों को बदलकर एक तरह से संगठन को जहां चाकचौबंद करने का प्रयास किया है, वहीं वह मतदाताओं को यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि उनकी आकांक्षाओं को भी राजनीतिक तौर पर ध्यान रखा जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान के बाद योगी आदित्य नाथ दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें दूसरा कार्यकाल मिला है। फिर शासन का योगी मॉडल भी भाजपा शासित राज्यों में लगातार लोकप्रिय होता गया है। इसलिए योगी के सामने चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अपनी कामयाबी दिखाएं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व की भी परीक्षा है। शायद यही वजह है कि जिलाध्यक्षों को बदलने के लिए यह कवायद की गई।

उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की राह इसी राज्य से होकर जाती है। सिर्फ नरसिंह राव का कार्यकाल ऐसा रहा, जिसे इस कहावत के हिसाब से अपवाद कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा यानी अस्सी सीटें आती हैं। सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में भाजपा को जहां 62 सीटें मिलीं, वहीं उसके सहयोगी अपना दल को दो सीटें मिलीं। हालांकि इसके पहले के चुनाव में भाजपा को राज्य की 73 सीटें मिली थीं। उसके पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, उसे बेहतर भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन संगठन और रणनीति के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कमाल किया और तीस सालों के अंतराल के बाद अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी शायद ऐसा ही कमाल साल 2024 के आम चुनावों में दिखाना चाहती है। जिलाध्यक्षों के बदलाव को भाजपा की इसी कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में 98 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें से 29 जिलों के पुराने अध्यक्षों पर ही भरोसा किया है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर और बीजेपी के राजनीतिक सफर का शक्तिपुंज अयोध्या जनपद प्रमुख हैं। आगरा और बरेली में भी पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। पार्टी ने इसके साथ ही वाराणसी और गोरखपुर जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ ही महानगर अध्यक्षों को भी बनाए रखा है। माना जा रहा है कि 29 जिलाध्यक्षों पर भरोसा बनाए रखने की वजह है, वहां हुए पंचायत और नगर निगम चुनावों में पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन। एक तरह से कह सकते हैं कि इन जिलाध्यक्षों पर भरोसा जताकर पार्टी ने माना है कि इनकी ही अगुआई में पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में फिर से अपना दमखम दिखाने में मदद मिलेगी।

भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य को संगठन के लिहाज से छह क्षेत्रों में बांट रखा है। इनमें पार्टी ने सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र से 17 जिलाध्यक्षों को बदला है। वहीं कानपुर क्षेत्र में 13 जिलों को नए अगुआ दिए गए हैं। इसी तरह ब्रज, काशी और अवध क्षेत्र के दस-दस जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इस तरह गोरखपुर क्षेत्र में 09 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। पार्टी ने सबसे ज्यादा बदलाव पश्चिमी क्षेत्र में किया है। इस इलाके में 19 जिला इकाइयाँ हैं, जिनमें से 17 के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इस इलाके में हालांकि गाज़ियाबाद महानगर व सहारनपुर जिलों के अध्यक्षों को नहीं बदला गया है। जाटलैंड के रूप में विख्यात इस इलाके में राज्य की 14 लोक सभा सीटें आती हैं। पिछले कुछ चुनावों से जाट लैंड को लेकर भाजपा चिंतित है। इसकी वजह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ समझौता है। पश्चिमी क्षेत्र में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी भी सेंध लगाने में कामयाब रही थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का खामियाजा उसे उठाना पड़े।

नए बने जिला अध्यक्षों में तकरीबन आधे जिला अध्यक्ष ऐसे रहे, जो पहले से ही संगठन में काम कर रहे थे। कोई जिले में महामंत्री था, कोई जिला उपाध्यक्ष था, तो कोई जिले में ही मंत्री था। कार्यकर्ता पहले की नीति की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। जिसमें करीब सात महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में पार्टी के कई अभियान हाल ही में संपन्न हुए हैं, कुछ चल रहे हैं और तमाम नए अभियान आने वाले दिनों में शुरू होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जारी सेवा पखवाड़ा भी शामिल है। माना जा रहा है कि अगर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और पहले से संगठन में काम नहीं कर रहे लोगों पर भरोसा जताती तो उसके लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती थीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नए व्यक्ति को कमान दी जाती तो उसे अपने संगठन और उसकी चुनौतियों को समझने में दिक्कत होती। जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता था।

पार्टी ने इस बदलाव में जातीय संतुलन साधने की भी भरपूर कोशिश की है। पार्टी ने सबसे ज्यादा भरोसा अन्य पिछड़ा वर्ग पर जताया है। राज्य में करीब 52 प्रतिशत आबादी इसी वर्ग से आती है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए हर चुनाव में भाजपा पर इस वर्ग ने भरोसा जताया है। शायद यही वजह है कि इस बार के बदलाव में पिछड़े वर्ग के बहुत लोगों पर भरोसा जताया गया है। बदले गए जिलाध्यक्षों में तीस इसी वर्ग से आते हैं। आमतौर पर जिलास्तरीय सांगठनिक फेरबदल में महिलाओं पर कम ही भरोसा जताया जाता है। इस बार भी पार्टी ने सिर्फ चार महिलाओं पर ही भरोसा जताया है। हाल के दिनों में ब्राह्मण मतदाताओं के एक वर्ग में पार्टी को लेकर मायूसी देखी गई। शायद यही वजह है कि इस बदलाव में बीस ब्राह्मणों को भी जगह दी गई है। पार्टी ने बलिया से जहां पूर्व विधायक संजय यादव पर भरोसा जताया है तो वाराणसी से पूर्व विधान परिषद सदस्य हंसराज वर्मा को ही कमान दी गई है। पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची में 21 जहां ठाकुर यानी क्षत्रिय बिरादरी के हैं, वहीं पांच दलित वर्ग से आते हैं। पार्टी के कोर वोटर वर्ग में सम्मिलित भूमिहार वर्ग के तीन और कायस्थ वर्ग के पांच लोगों को मौका दिया गया है। इसी तरह वैश्य समुदाय के दस लोगों को जिलाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में पार्टी ने अपनी तरह से सांगठनिक सेना सजाने की कोशिश की है। जिसका मकसद लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए दिल्ली की राह आसान करना है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-11)

गतांक से आगे...

यह उपनिषद् अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें पराम्बा त्रिपुरसुन्दरी के श्रीचक्र पर आसीन होकर सर्वशक्तिमयी रूप को प्रकट करने का वर्णन है। सर्वप्रथम शिव के ईश्वरत्व का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शक्ति के सहयोग से ही वह शिव कहे जाते हैं। तत्पश्चात् तीनों शरीरों (स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण) में श्रीचक्र की भावना का विशद वर्णन है। इसके बाद देवशक्तियों के आवाहन, आसन, पाद्य आदि उपचार की भावना वर्णित है। अन्त में भावना का फल बताते हुए कहा गया है कि जो भी साधक इस प्रकार तीन मुहूर्त तक भावना - परायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है। वह एकमात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। वही साधक शिवयोगी कहलाता है। इस प्रकार यह उपनिषद् पूर्ण हो जाती है।

किस हेतु से शरीर में श्रीचक्रत्व सिद्ध होता है ? नौ छिद्रों से युक्त यह देह है तथा (विमल से लेकर ईशान तक नौ शक्तियों से सम्पन्न यह श्रीचक्र है। इस देह की माता कुरुकुल्ला बलि देवी एवं पिता के रूप में वाराही हैं। देह के आश्रय रूप में धर्मादि चारों पुरुषार्थ ही इसके चार समुद्र के रूप में हैं। यह शरीर ही नवरत्न द्वीप है। इस द्वीप की आधारभूता शक्तियाँ (योनिमुद्रा आदि सर्वसंक्षोभिणी पर्यन्त) महात्रिपुरसुन्दरी आदि नौ हैं। त्वचा आदि सप्त धातुओं एवं अनेक अन्तः-बाह्य विकारों से युक्त नानाविध संकल्प-विकल्प ही कल्पवृक्ष है। (उस परमात्मा से भिन्न रमणीय नानाविध) तेजस् स्वरूप सा जीव ही उद्यान है। जिह्वा द्वारा आस्वादित किये जाने वाला मधुर, अम्ल, तिक्त (तीखा), कडुवा, कषैला एवं नमकीन रस आदि छः ऋतुएँ हैं। क्रिया नामक जो शक्ति है, वही पीठ है। कुण्डलिनीरूपी ज्ञानशक्ति ही गृह है। इ'छाशक्ति ही महात्रिपुरसुन्दरी नामक आराध्या भगवती है। ज्ञाता ही होता (हवन करने वाला), ज्ञान ही अर्घ्य एवं ज्ञेय (ज्ञातव्य तत्त्व) ही हविरूप है। ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय को भेदरहित मानना ही श्रीचक्र का पूजन है। अणिमादि सिद्धियों (अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इ'छा, प्राप्ति और सर्वकाम मुक्ति) का सम्बन्ध नियति (प्रकृति निर्धारण) सहित श्रृंगार, वीर, करुण आदि नौ-रसों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पुण्य एवं पाप से युक्त ब्राह्मी आदि आठ शक्तियाँ हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पैर, मल-मूत्रेन्द्रियाँ तथा मन आदि विकार ही (मूल प्रकृति से उत्पन्न षोडश शक्तियाँ हैं। वचन (बोलना), **क्रमशः**

नि:शक्त बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दी

सतीश जांगड़े

मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के नंदनी गाँव में रहता हूँ। मैं बचपन से ही पोलियो का शिकार हूँ। 7 लेकिन मेरे लिए परेशानी सिर्फ इतनी ही नही थी, परिवार की गरीबी भी मेरी अनचाही विरासत थी। मेरे पिता एक कताई मिल में मजदूरी करते थे। घर की खराब आर्थिक स्थिति ने नौवीं कक्षा के बाद मुझसे स्कूल छीन लिया। पोलियो की वजह से मैं ठीक से चल नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं पूरी तरह निःशक्त था। सरकारी प्रमाणपत्र में भी मेरे शरीर को मात्र बयालीस फीसदी अक्षम माना गया है, जिसका अर्थ है कि मेरे शरीर का बड़ा हिस्सा सामान्य है।

बारह की उम्र में मैंने परिवार को सहारा देने के लिए काम करना शुरु कर दिया। मैं गाँव के पशुपालकों से दूध एकत्रित करता और साइकिल की मदद से करीब चौबीस किलोमीटर दूर शहर में जाकर उसका वितरण करता । मैं यह काम खत्म करने के बाद स्कूल जाता था। लेकिन आधे शरीर के चलते वह दोहरी भूमिका मैं ज्यादा दिन निभा नहीं सका। नतीजतन मेरी पढ़ाई छूट गई। बाद में मैंने दो सौ रुपये मासिक वेतन वाली दूसरी नौकरी शुरू कर दी। गाँव में ही वित्तीय प्रबंधन सँभालने वाले एक समुदाय के लिए काम करते हुए मैंने तेईस साल गुजार दिए इस दौरान में हमेशा से ही अपने जैसे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चहता था। अपनी इसी सोच के विस्तार के लिए दस साल पहले मैंने एक संस्था का गठन किया। मेरे लिए जरूरी था कि किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से पहले जरूरी धन इकट्ठा कर लिया जाए। शुरु में मैंने यही सोचा था कि जो लोग चिकित्सा की मदद से नि:शक्तता के श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, उनकी मदद की जाए। कुल जमा पाँच हजार की तनख्वाह वाली नौकरी करते हुए मेरे लिए ऐसा निर्णय करना आसान नहीं था। लेकिन एक अच्छी नीयत को लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। संस्था बनी, तो जरूरतमंद लोगों ने मुझसे संपर्क किया। महाराष्ट्र के आठ अलग-अलग जिलों के आठ निःशक्त बच्चे मदद की उम्मीद में मेर पास आए। ये बच्चे मेरे बचपन के प्रतिरूप थे। मैंने इनके लिए श्रवणबल नि:शक्त वस्तिगृह नाम से एक आश्रय स्थल की शुरुआत की। मेरी पत्नी इस पूरे सफर में मजबूती के साथ मेरे साथ रही। वही बच्चों के लिए खाना पकाती, उनके कपड़े धोती और हॉस्टल के दूसरे काम भी निपटाती ।

इन बच्चों का संपूर्ण खर्च मैं और मेरे सहयोगी उठाते। यहाँ तक कि हॉस्टल की सुरक्षा के लिए मेरा एक मित्र बच्चों के साथ रहता। इन बच्चों की सेवा करते-करते मुझे आनन्द आने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि इनकी पूरी तरह मदद करने के लिए डेढ़ साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी। अल्प आय वाले परिवारों से आने वाले इन बच्चों को मेरे अनुभवों की जरूरत थी। लोगों से मिले चंदे और अपनी बचत की मदद से मैंने अब तक चालीस ऑपरेशनों में निःशक्तों की मदद की है। इसके अलावा मैंने विभिन्न सरकारी और चैरिटी मदों से दो सौ कृत्रिम अंग, चार सौ सुनने की मशीन और सैकड़ों व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की है। मेरा सपना है कि मैं इन बच्चों के लिए अपना खुद का विशेष स्कूल खोलूँ। मैं इस योजना पर काम कर रहा हूँ।

सांसद तैयारी करते नहीं, ऊपर से सरकार की रणनीति

अजय सेतिया

जिन दिनों संसद की लाईब्रेरी पुराने ससंद भवन की पहली मंजिल पर हुआ करती थी, उन दिनों सांसद अक्सर संसद की पुरानी कार्यवाही के पन्ने पलटते, संविधान सभा के भाषण पढ़ते और राजनीतिक इतिहास की किताबें अलॉट करवाते दिख जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जार्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवानी, जसवंत सिंह, कुमार मंगलम, सोमनाथ चटर्जी, मधु लिमए को नब्बे के दशक में मैंने खुद लाईब्रेरी में अक्सर देखा है। शिवराज पाटिल के लोकसभा अध्यक्ष रहते 1993 में यह नई विशाल लाइब्रेरी बनी थी। अब यह लाईब्रेरी अक्सर वीरान पड़ी रहती है। पिछले कुछ समय में जब भी लाईब्रेरी में जाना हुआ तो जयराम रमेश के अलावा कभी कभार ही कोई सांसद दिखाई दिया। सांसद वहां जाते भी हैं, तो अक्सर अखबारों और पत्रिकाओं के पन्ने पलटते दिखाई देते हैं। किताबों वाले सेक्शन में जाते ही नहीं।

सांसदों की पढ़ने लिखने की आदत खत्म हो रही है, जबकि संसद की लाईब्रेरी देश की दूसरी बड़ी लाईब्रेरी है। इसका असर सांसदों की बहस के गिरते स्तर में भी दिखाई देने लगा है। विषयों के गहन अध्ययन के बिना होने वाली बहसें हल्की फुल्की हो गई हैं, कम ही सांसदों के भाषण में गहराई देखने को मिलती है। बहस में भाग लेने के लिए भी अब इक्का दुक्का सांसद लाईब्रेरी में जाता है। राजनीतिक दलों के कर्मचारी ही सांसदों को मेटीरियल उपलब्ध करवाते हैं, वे उसी के आधार पर ही बोल कर खानापूर्ति कर देते हैं। महिला आरक्षण पर बहस के दौरान सांसदों की ओर से जो मुद्दे उठाए गए, उनमें से कुछ बहुत ही हास्यास्पद थे। कुछ ऐसे तर्क दिए गए, जिन्हें सुन

कर सामान्य नागरिकों को भी आश्चर्य होता होगा। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस का बिल बताने और अपने पति राजीव गांधी को श्रेय देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिल पास होने से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। जबकि सच्चाई यह है कि राजीव गांधी के समय महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस में गहरे मतभेद थे, यहाँ तक कि पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी ने संविधान संशोधन कर के जब महिला आरक्षण लागू किया था, तो कांग्रेस में उस पर भी मतभेद थे। इसीलिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का बिल प्रारूप भी राजीव गांधी सरकार के समय तैयार नहीं किया गया था।

अब अगर यह राजीव गांधी का व्यक्तिगत सपना था, तो उसे न राजीव गांधी ने खुद पूरा किया, न उनके बाद पांच साल चली कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार ने पूरा किया, न दस साल चली मनमोहन सिंह सरकार ने पूरा किया। अगर वह 2010 में राज्यसभा में बिल पास करवाने की बात करती हैं, तो वह बिल 2014 में पन्द्रहवीं लोकसभा भंग होने के साथ ही अपनी मौत मर चुका है। यही दोनों गलतियां पहले दिन बिल पेश होते समय अधीर रंजन चौधरी ने भी की थीं, लेकिन उन्हें अगले दिन भी दोहराया गया।

कांग्रेस बिल का समर्थन कर रही है, लेकिन आज भी कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कार्ति चिदंबरम ने बिल के उस हिस्से का खुलेआम विरोध किया है जिसमें कहा गया है कि अगली जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन किया जाएगा। कीर्ति चिदंबरम ने कहा है कि जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। जबकि यह बिल तो 2002 में ही संसद अनुच्छेद 82 में संशोधन पास करके पास कर चुकी है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा। उससे पहले लोकसभा या विधानसभाओं की सीटें बढाने पर रोक लगाई गई थी। कार्ति चिदंबरम क़ानून के अच्छे जानकार हैं, लेकिन संसदीय इतिहास का ज्ञान तो संसद की लाईब्रेरी में बैठने पर ही मिलेगा। कांग्रेस समेत बिल का समर्थन करने वाले सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने जनगणना के बाद आरक्षण का विरोध करते हुए 2024 के चुनाव से ही आरक्षण लागू किए जाने की मांग की है। लेकिन उन्हें किसने रोका है, वे 2024 के चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देकर मोदी के नहले पर दहला मार दें। संसद की नई इमारत में पहले ही दिन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कुछ ऐसी अज्ञानता में भटकते दिखाई दिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में गलती निकाली कि जिस सेंगोल को वह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बता रहे हैं, वह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है। उन्होंने इतिहास का वह पन्ना पढ़ कर सुनाया, जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार ने नेहरू से पूछा था कि भारतीय परंपराओं में सत्ता हस्तांतरण की कोई विधि है क्या। नेहरू ने इस बारे राजगोपालाचारी से पूछा तो उन्होंने चोल राजाओं की परंपरा को सामने रखा, जिसमें हिन्दू धार्मिक मठ अधीनम नए राजा को सेंगोल सौंपता था, जिसे राजदंड कहा जाता था, और जिसे सेंगोल सौंपा जाता था, उससे न्याय की अपेक्षा की जाती थी।

परंपरा के मुताबिक़ सेंगोल अधीनम मठ को सौंपना था, और अधीनम मठ के प्रतिनिधि ने जवाहर लाल नेहरू को उनके घर पर पूरे शानोशौकत के साथ सेंगोल सौंपा था। नेहरू की क्योंकि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे एक कोने में रखवा दिया। उसी सेंगोल को दुबारा बनवा कर मोदी ने इसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के साथ स्थापित करवाया है। कांग्रेस सत्ता हस्तांतरण के इस सनातन तरीके को न नेहरू के जमाने में मानती थी, न अब मानती है।

तमिलनाडु में सनातन विरोधी द्रमुक के साथ गठबंधन के चलते तमिल सनातन परंपरा का विरोध इस समय भी कांग्रेस की मजबूरी है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने नेहरू को सेंगोल नहीं सौंपा था, इसलिए यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है। अधीर रंजन अगर संसद भवन की लाईब्रेरी में कुछ देर बैठते तो उन्हें पता चलता कि अधीनम मठ के स्वामी ही नए राजा को सेंगोल सौंपते थे, बिटिश गवर्नर जनरल से सेंगोल लेने का सवाल ही नहीं था। प्राचीन भारतीय परंपराओं से ईसाई अंग्रेजों को क्या लेना देना था। उन्होंने तो नेहरू से कहा था कि वह अपनी परंपराओं का निर्वाहन करें, और नेहरू ने किया था। समाजवादी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने 2010 में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ मनमोहन सरकार गिराने की धमकी दे दी थी। उनकी बहू डिम्पल यादव उन्हीं के देहांत से खाली हुई मैनपुरी सीट के उपचुनाव से सांसद चुनी गई हैं।

हिन्द स्वराज्य

सच्ची सभ्यता कौन सी ?

प्रश्न- आपने रेल को रद कर दिया, वकीलों की निन्दा की, डॉक्टरों को दबा दिया। तमाम कल काम को भी आप नुकसानदेह मानेंगे, ऐसा मैं देख सकता हूँ। तब सभ्यता कहें तो किसे कहें?

उत्तर- इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता हिन्दुस्तान ने दिखायी है, उस सभ्यता को पाने में दुनिया में कोई नहीं पहुँच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोये हैं, उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आयी। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गयी, जापान पश्चिम के शिकंजे में फँस गया और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा-टूटा जैसा भी हो, हिन्दुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। जो रोम और ग्रीस गिर चुके हैं, उनकी किताबों से यूरोप के लोग सीखते हैं। उनकी गलतियाँ वे नहीं करेंगे ऐसा गुमान रखते हैं। ऐसी उनकी कंगाल हालत है, जब कि हिन्दुस्तान अचल है, अडिग है। यही उसका भूषण है। हिन्दुस्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वह ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञान है कि उससे जीवन में कुछ फेरबदल कराये ही नहीं जा सकते। यह आरोप हमारा गुण है, दोष नहीं। अनुभव से जो हमें ठीक लगा है उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अकल देने वाले आते-जाते रहते हैं, पर हिन्दुस्तान अडिग रहता है। यह उसकी खूबी है, यह उसका लंगर है। सभ्यता वह आचरण है, जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मानी हैं नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब अपने मन और इन्द्रियों को बसमें रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को (अपनी असलियत को) पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे जो उलटा है वह बिगाड़ करने वाला है। बहुत से अंग्रेज लेखक लिख गये हैं कि ऊपर की व्याख्या के मुताबिक हिन्दुस्तान को कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहता। यह बात ठीक है। हमने देखा कि मनुष्य की वृत्तियाँ चंचल हैं। उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे-जैसे ज्यादा दिया जाय वैसे-वैसे ज्यादा माँगता है। ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बाँध दी।

क्रमशः ...

मोदी की मुहिम से क्यों डरे हुए हैं क्षेत्रीय दल और कांग्रेस?

अनिल तिवारी

एक देश एक चुनाव को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक विशेष सत्र के बाद 23 सितंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में अस्थाई के टैग वाले एजेंडा के साथ आहूत विशेष सत्र के दौरान इससे जुड़े किसी विधेयक के आने की संभावना न के बराबर है। लेकिन हाल के बरसों में हर मसले पर जल्दबाजी में रहने वाली कांग्रेस पार्टी शायद कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, उसे अब भी आशंका है कि अक्सर सरप्राइज देने के लिए चर्चित प्रधानमंत्री कोई मूव ले सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहले से स्थापित लाइन से इतर हटकर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है।

इतिहास गवाह है कि 60 के दशक तक एक देश एक चुनाव कांग्रेस का मुद्दा रहा है। बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी इसके पक्ष में लगातार चर्चाएं की हैं। अब जब मौजूदा सरकार ने चुनाव खर्च में भारी कमी आने की बात को प्रमुखता से आगे कर इस विषय को उठाया है, तो विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है, संविधान पर हमला बता रही है। राजनीति में किसी विषय पर सहमति-असहमति अपनी जगह है। लेकिन विषय से संबंधित संवाद में हिस्सा लेना लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ व्यवहार माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दा चाहे आसान हो अथवा जटिल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद होना ही चाहिए। संवाद में जहां कमी है उस विषय को अवश्य विपक्ष को उजागर करना चाहिए। जैसे सरकार ने इस विषय पर विचार के लिए जो समिति बनाई है, उसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को रखा गया था। लेकिन पार्टी के दवाब में उन्होंने समिति से अलग होने की घोषणा कर दी।

कांग्रेस यह भी कह सकती थी कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा पूरे देश को प्रभावित करेगा, इसलिए समिति का आकार बड़ा होना चाहिए था। लोकसभा के साथ-साथ विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं इसलिए इस समिति में राज्यों के मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों को भी रखा जाना क्या बेहतर नहीं होता? एक देश एक चुनाव पर होने वाले खर्च पर ही व्यापक पैमाने पर बहस की मांग करती क्योंकि खर्चे में कमी के दावे को सरकार के कानून मंत्री के तर्कों ने ही सिर के बल उल्टा खड़ा कर दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ध्यान दिलाया है कि एक ईवीएम मशीन का जीवनकाल

15 वर्ष भी मानें तो एक साथ चुनाव की व्यवस्था में एक मशीन का अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ तीन या चार बार ही उपयोग किया जाएगा, जिससे हर 15 साल पर उन्हें बदलने पर बहुत भारी खर्च होगा।

पीछे के पन्नों को पलट कर देखें तो एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के विचार अलग-अलग रहे हैं और वक्त के साथ बदलते भी रहे हैं। मगर एक मोटा सा विभाजन हमेशा ही रहा है। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने इस विचार का हमेशा समर्थन किया है, वहीं छोटे क्षेत्रीय दल इसको लेकर आमतौर पर आशंकित रहे हैं। वर्ष 2014 में भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक क्षेत्रीय दलों के सहारे खड़ा होने का प्रयास करती रही है। संभव है क्षेत्रीय दलों को फौरी तौर पर साधे रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया हो। लेकिन यहां उल्लेखनीय यह है कि छोटे बड़े 38 दलों के समूह राजग की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री की ओर से यह प्रस्ताव आया है, और 26 दलों को मिलाकर बने इंडिया के घटक दल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए विरोध किया है।

छोटे और क्षेत्रीय दलों को इस बात का डर है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू हुआ तो चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द-गिर्द सिमट जाएंगे, स्थानीय मुद्दों की हवा निकल जाएगी। चूंकि देश में मतदान को लेकर समझ पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अधिकांश मतदाता आज भी अपने मतों का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में यह अपेक्षा करना कि एक मतदाता लोकसभा में अन्य मुद्दे पर मतदान करेगा और विधानसभा या पंचायत के लिए अन्य मुद्दे पर अपना वोट डालेगा, सही नहीं है। ऐसे में जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों की भी अनदेखी होगी। दूसरा डर यह है कि एक साथ चुनाव होने पर जनता के बीच बड़ी पार्टियां तो दिखाई देगी लेकिन साधन संसाधन के अभाव में छोटी पार्टियां लाइमलाइट से दूर हो जाएगी। क्षेत्रीय दलों पर राष्ट्रीय दलों की तुलना में मीडिया का भी ध्यान कम ही जाएगा। उन्हें डर है कि मीडिया के अभाव में जनता उनके विचारों से अवगत ही नहीं हो पाएगी।

तीसरा मामला खर्चे से जुड़ा हुआ है। बड़ी पार्टियों के पास संसाधन बहुत हैं लेकिन छोटे दलों के पास सीमित है। छोटे दलों को डर है कि अपने सीमित साधन के साथ अपने चुनाव प्रचार को लेकर आधिकाधिक जनता के बीच नहीं जा सकते। चौथे, सरकारों के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यों से जनता के मत प्रभावित होते हैं। ऐसे में केंद्र के प्रभाव से राज्य या राज्य के प्रभाव से क्षेत्र विशेष का चुनाव प्रभावित हो सकता है। पांचवा डर है चुनाव में बड़े चेहरों के प्रभाव का। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। मतदाताओं का स्वाभाविक लगाव बड़े कद के नेताओं के प्रति होता ही है। कांग्रेस ने अपना पहला तीन चुनाव पंडित नेहरू के नाम पर लड़ा, अब 2014 से भाजपा अपना चुनाव नरेंद्र मोदी को आगे कर लड़ रही है। छोटे और क्षेत्रीय दलों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है गठजोड़ का। किस दल के साथ हाथ मिलाना है और किस दल से किनारा करना है, यह निर्णय छोटे दलों के लिए कठिन हो सकता है। वर्तमान में अलग-अलग चुनाव होते हैं तो उनके पास अवसर की विविधता भी होती है, लेकिन एक देश एक चुनाव के बाद उन्हें किसी एक बरगद के नीचे ही जाना होगा।

बहरहाल छोटे और क्षेत्रीय दलों की तुलना में कांग्रेस पार्टी एक देश एक चुनाव के विरोध में अधिक मुखर है। वर्ष 1957 में कांग्रेस के एकाधिकार और वर्चस्व को तोड़कर सत्ता में आई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने वाली, आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 6 साल कर देने वाली कांग्रेस पार्टी इसे संघीय ढांचे का अतिक्रमण बता रही है। उम्मीद की जा रही थी कि हैदराबाद में बैठी कांग्रेस कार्य समिति एक देश एक चुनाव के मसले पर कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आएगी लेकिन संसद का विशेष सत्र शुरू होने के पहले ही कांग्रेस कार्य समिति ने एक देश एक चुनाव के विचार को खारिज करते हुए इसे संविधान और देश के संघीय ढांचे पर हमला बताकर फिर से अपरिपक्व सोच का उदाहरण ही प्रस्तुत किया है।

जी20 घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का द्योतक

आचार्य राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी

भारत की अध्यक्षता में दिल्ली के भारत मंडपम में जी20 का शिखर सम्मेलन उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। देश के यशस्वी, ऊर्जावान एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस सम्मेलन ने बुलंदियों का नया आसमान छुआ। भारत की कूटनीतिक सफलता का ही परिणाम है कि सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया एवं विश्व की 85 प्रतिशत जीडीपी वाले अफ्रीकन यूनियन के जी20 समूह में प्रवेश सहित ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर सहमति बनी। पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम एवं भविष्य की राह की दृष्टि और व्यापक मानवतावादी वैश्विक दृष्टिकोण के कारण इस घोषणापत्र की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ध्यातव्य है कि पूर्व में रूस-यूक्रेन के विषय को लेकर इस घोषणा-पत्र को स्वीकार्यता मिलने में समस्या आ रही थी। इस गतिरोध को दूर करने हेतु भारत ने कूटनीति का परिचय देते हए घोषणा-पत्र के पैराग्राफ में ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे सहजता से स्वीकृति मिली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही सभी को अन्य देशों की अखंडता एवं संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विपरीत अधिग्रहण की धमकी या शक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी देना भी कतई स्वीकार्य नहीं है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो जी20 सदस्यों की अर्थव्यवस्था को गति देने एवं टिकाऊ आर्थिक सुधार लाने हेतु निजी उद्यमशीलता की भूमिका पर सहमति बनी है। भारत की दृष्टि से देखें तो भारत, मिडिल ईस्ट एवं यूरोप के बीच व्यापारिक कॉरिडोर की संकल्पना साकार होने से भारत के व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गति आएगी। इसके इतर जी20 सदस्यों ने विकासशील देशों में निवेश परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता दूर करने एवं टिकाऊ, संतुलित, सर्वसमावेशी, दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता हेतु व्यापक आर्थिक एवं संरचनात्मक नीतियों को लागू करने पर सहमति बनी है। फलत: समान विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता की मजबूती से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री मोदी कि ने दोहराया जी20 की हमारी अध्यक्षता का संदेश है एक पृथ्वी, एक कुटुम्ब एवं एक साझा भविष्य'। अत: जी20 घोषणा-पत्र सतत, सर्वसमावेशी, प्रकृति-केन्द्रित विकास के मॉडल पर आधारित है। इसमें विकास हेतु सतत हरित मार्ग की परिकल्पना की गई है। इसी के अंतर्गत भारत की पहल पर विश्व जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत भी हुई। शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल पहल करने का आह्वान किया। निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध वैश्विक मुहिम के लिए व्यापक रणनीति जैसे इस हेतु वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने आदि पर सहमति बनी है। घोषणा की गई कि हम सब आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की क्षति के मध्य संतुलित जलवायु एजेंडे के साथ धरती की सुंदरता एवं जीवन की गरिमा सुनिश्चित करेंगे। घोषणापत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ ही प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े फायदे एवं नुकसान को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष समर्थक व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया गया जिससे वह ज्यादा उपयोगी हो सके। आतंकवाद एवं वैश्विक भ्रष्टाचार को खत्म करने, पारंपरिक विरासत को संभालने तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के तीव्र प्रसार के प्रयासों पर भी भारत की पहल को स्वीकारता मिली है। भारत ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सर्वथा सक्षम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिवर्तनकारी पहलुओं से सदस्य देशों को परिचित करवाया। सभी ने माना कि शिक्षा में सृजनात्मकता, तर्कसंगत सोच, अनुसंधान, कौशल विकास, उद्यमिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर शिक्षा के नूतन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

राजनीति के लिए पत्रकारों में बंटवारा और बहिष्कार क्यों?

उमेश चतुर्वेदी

कांग्रेस के लंबे समय तक एक प्रवक्ता रहे विट्ठल नरहरि गाडगिल। राजनीति में आने से पहले फ्री प्रेस जर्नल के पत्रकार रहे गाडगिल की एक विशेषता थी। पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग में अपनी बात तो वे कुशलता से कह लेते थे, लेकिन जब कांग्रेस और उनके नेताओं से जुड़े असहज सवाल पत्रकारों की ओर से उछाले जाते तो वे बहरे हो जाते थे। उनका एक ही जवाब होता था कि उन्होंने सुना नहीं। असहज सवालों या फिर जिन सवालों का जवाब देना नेता जरूरी नहीं समझते उसको नजरअंदाज कर देने के उनके कई तरीके होते हैं। वीएन गाडगिल का यह अपना एक तरीका था। इस मामले में कांग्रेस पार्टी शायद सबसे उदार रही है कि चाहे जितना कठोर सवाल पूछा जाए उसका नेता संतुलित ही रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर वह संतुलन समाप्त होने लगा है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से मीडिया में 14 एंकरों के बहिष्कार का ऐलान किया है, वह देश ही नहीं कांग्रेस के पारंपरिक चरित्र के लिहाज से भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है। ऐसा नहीं कि पहली बार कांग्रेस विपक्ष में आई है। वाजपेयी के शासनकाल के दौरान भी कांग्रेस प्रवक्ताओं की ओर से कभी पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से पत्रकारों को संभालने की कमान तब कपिल सिब्बल, अजीत जोगी, मार्गरेट अल्वा या एस जयपाल रेड्डी संभालते रहे। हां, उस दौर में उसके मीडिया सेल में कार्यरत और अब भाजपा के केरल के नेता बन चुके टॉम वडक्कन राष्ट्रवादी पत्रकारों को अक्सर मीडिया ब्रीफिंग से निकाल बाहर करते रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता तब असहज सवालों से बचने के लिए अपने खेमे के पत्रकारों को मुस्तैद रखा करते थे और बीच में ही वे अपने सहज सवाल लेकर लपक पड़ते थे। कुछ पत्रकार तो कांग्रेस के पक्ष में ऐसी लामबंदी करते रहे कि टेलीविजन चैनलों में उन्हें कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरह बुलाया जाने लगा और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। लेकिन पुराने कांग्रेसी प्रवक्ताओं की तुलना में जरा आज के कांग्रेसी प्रवक्ताओं को देखिए। कुछ महीने पहले एक टीवी बहस में कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा आपा खो बैठे कि बहस में शामिल एक नेता पर पानी का गिलास फेंक दिया। उससे उस बहस की एंकरिंग कर रहे सज्जन का कोट भी भीग गया था। संयोग से वह सज्जन इंडिया एलायंस की बहिष्कार लिस्ट में नहीं हैं। दिल्ली में तो ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन वामपंथी वर्चस्व के दौर में पश्चिम बंगाल में एक हद तक पत्रकारों को विचारधारा के आधार पर बंटवारे की प्रवृत्ति रही है। वामपंथी दलों को जब भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना होता है तो वे खुद को कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक साबित करने लगते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे का शासन ऐसा नहीं था जहां सिर्फ लोकतांत्रिक आनंद ही आनंद था। वाममोर्चे की राजनीति की संस्थागत तानाशाही को शायद ही कोई पत्र या पत्रिका रिपोर्ट करती थी। आज का टेलीग्राफ अखबार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, वैसी शब्दावली आज भी वह न तो ममता के खिलाफ करता है और ना ही अतीत में कभी वाममोर्चे के शासनकाल के खिलाफ करता रहा। आशय यह है कि वाम वर्चस्व के दौर में न सिर्फ राजनीति को विचारधारा के आधार पर बांटा गया बल्कि साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता हर जगह विचारधारा का यह बंटवारा दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन द्वारा विचारधारा के आधार पर एंकरों का बहिष्कार मानों उसी बंटवारे का विस्तार है।

भारत की चिंताओं की अनदेखी कर रहे ट्रूडो

हर्ष वी. पंत

यह तो होना ही था। बरसों से भारत और कनाडा के बीच न केवल अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था बल्कि दोनों तरफ के राजनीतिक नेतृत्व में भी एक-दूसरे के प्रति बेरुखी बनी हुई थी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाकर दोनों देशों के संबंधों को ऐसी अतल गहराइयों में पहुंचा दिया है, जहां से उबरना आसान नहीं होगा। भारत ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है। दोनों तरफ से राजनयिकों का निष्कासन भी हुआ। भारत ने जवाब में खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए कनाडा सरकार से वहां सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ तत्काल कारगर कानूनी कदम उठाने की मांग की है।

पिछले दिनों जी20 शिखर बैठक के दौरान नई दिल्ली में ट्रूडो का रूखा स्वागत भी इस बात का संकेत था कि उनकी सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्तों में कितना गहरा अविश्वास आ गया है। शिखर बैठक में मोदी और ट्रूडो के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। जो थोड़ा-बहुत संवाद दोनों के बीच हुआ, उसमें भी मोदी ने यह बात उठाई कि कनाडा में भारत विरोधी आतंकवादी तत्वों की नकेल कसने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। ट्रूडो कई लिहाज से दोनों देशों के रिश्तों फलते-फूलते रिश्तों में आई गड़बड़ियों के प्रतीक बन चुके हैं। 2016 में नाकाम हुई अपनी पहली यात्रा के बाद वह कभी भी भारत के साथ तालमेल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। उनका यह ताजा बयान भी कि 'सुरक्षा एजेंसियां कनाडियाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारत सरकार के एजेंटों के संभावित जुड़ाव संबंधी विश्वसनीय आरोपों की तत्परता से जांच कर रही हैं'

जल्दबाजी में दिया गया लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे वैश्विक मंचों पर अनदेखी और घरेलू मोर्चे पर पैदा हुए तमाम संकटों के बीच खुद को एक विश्वसनीय नेता के रूप में पेश करने की मंशा ज्यादा है। वरना ट्रूडो जांच एजेंसियों के किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने का इंतजार तो कर ही सकते थे। लेकिन उन्होंने 'संभावित जुड़ाव' और 'आरोपों' के ही सहारे भारत पर हल्ला बोल दिया। भारत के लिए कनाडा के 1,70,000 से भी ज्यादा बड़ी प्रवासी सिख आबादी में बढ़ता अतिवाद लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। भारत ने इसे कनाडा सरकार के सामने समय-समय पर उठाया भी है। लेकिन ट्रूडो सरकार के साथ दिक्कत यह रही है कि भारत के साथ उसका रुख घरेलू राजनीति के अजेंडे से तय हो रहा है। इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। 2021 में जस्टिन ट्रूडो को बहुत कम अंतर से जीत मिली और उन्हें जगमीत सिंह 'जिम्मी' धालीवाल की अगुआई वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) का सहारा सरकार बनाने के लिए लेना पड़ा, जिसकी 24 सीटें हैं। ट्रूडो राजनीतिक अनिश्चितताओं से घिरे हैं और ऐसे में कम से कम 2025 तक उनके लिए एनडीपी का समर्थन बेहद अहम है।

किसान समर्थन से लेकर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई तक ट्रूडो और सिंह के बयान भारत-कनाडा रिश्तों में कड़वाहट घोलते रहे हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी पर सिख ग्रुपों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि 2018 में कनाडा के लिए आतंकवादी खतरों पर जारी की गई अपनी एक सार्वजनिक रिपोर्ट में सिख आतंकवाद और खालिस्तान का जिक्र करने के बाद पार्टी को इस रिपोर्ट की संशोधित प्रति छापनी पड़ी, जिसमें सिख आतंकवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। शायद यही वजहें हैं कि कनाडा में भारत विरोधी अतिवादी विचार दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो भारत की चिंताओं के प्रति पूरी उदासीनता बनाए हुए हैं। भारतीय अधिकारियों की तस्वीरों वाले खालिस्तानी पोस्टर वहां लगाए गए थे। भारतीय उच्चायोग परिसर पर हमला भी हो चुका है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या का दृश्य उकेरते हुए झांकियां निकाली गईं। भारत के सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ सिख आतंकवादियों की ओर से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं।

यहां तक कि जब भारत में जी20 शिखर बैठक हो रही थी, तब भी सिख्स फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन, जो भारत में बैन है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान पर जनमतसंग्रह करवा रहा था। लेकिन भारत की लगातार अपील के बावजूद ट्रूडो सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन सबकी अनदेखी करती रही। ऐसे हालात में, दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मौजूदा तल्खी के प्रभावों से बचाने की भी कुछ कोशिशें हुई हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। यही नहीं मुफ्त व्यापार समझौते पर मुहर लगाने की इच्छा भी दोनों तरफ है। लेकिन दोनों देशों के बीच तेज होते राजनीतिक मतभेदों के चलते व्यापार वार्ताएं भी स्थगित हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि कनाडा की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं उसकी घरेलू राजनीति की बंधक बन चुकी हैं। खतरा यह है कि हिंद-प्रशांत रणनीति का उसका पूरा महल ताश के पत्तों की तरह भहरा कर गिर सकता है।

महिला अधिकारों की पटकथा का गवाह रहा है पुराना संसद भवन

स्वाति

कहते हैं एडवर्ड लुटियन को उस समय के काउंसिल हाउस (बाद में संसद भवन) की डिजाइन की प्रेरणा मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर से मिली थी। यह 64 योगिनियों के प्रभाव का असर है या फिर समय की मांग लेकिन अब संग्रहालय का रूप लेने जा रहे उस संसद भवन में महिलाओं को लोकतंत्र में कानूनी रूप से बराबरी पर लाने में जो अहम भूमिका निभाई है उसी का परिणाम है कि आज नये संसद भवन में लोकसभा तथा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो सका है।

हिन्दुओं में बहुविवाह पर रोक हो या मुस्लिमों में तीन तलाक पर रोक, महिला सुरक्षा के लिए संसद का यह भवन एक स्वर्णिम इतिहास का साक्षी रहा है। शायद इसीलिए सोमवार को पुराने संसद भवन की विदाई और नये संसद भवन में प्रवेश के लिए बुलाये गये विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन की महिमा बताते हुए महिलाओं के मुद्दे को भी छुआ। अपने भाषण में उन्होने संसद में महिलाओं के विशेष योगदान को भी उल्लेखित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल लोकसभा स्पीकर के रूप में सुमित्रा महाजन के साथ अपने अनुभव और उनके योगदान को याद किया बल्कि सबसे कम उम्र की सांसद के रूप में चंद्रानी मुर्मू का जिक्र छेड़ा जो 25 वर्ष की उम्र में संसद सदस्य बनकर इस भव्य भवन में आ गयी थीं। उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता के बाद कुल 7500 संसद सदस्य बनकर इस भवन में प्रविष्ट हुए हैं जिसमें 600 महिला सांसद हैं। यह सच है कि लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पुराने संसद भवन ने भारतीय जनता को विशेष रूप से महिलाओं को बहुत कुछ दिया है।

देश के विकास में स्त्रियों के योगदान को समझते हुए ही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था- लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरुरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो उनके पीछे पीछे परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। यह सच है कि स्वतंत्रता के समय महिलाओं को अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था और उनकी स्थिति कई मामलों में बदतर थी। इसीलिए संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार देने के उद्देश्य से कई कानून बनाये गए थे।

संविधान का अनुच्छेद 14 सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता है। अर्थात कानून की नज़र में लिंग भेद के आधार पर भेद-भाव नहीं बरता जा सकता है और यह महिलाओं को भी वही मौलिक अधिकार देता है जो संविधान पुरुष वर्ग को देता है। इससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से उसे क़ानूनी सुरक्षा मिलती है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति देता है, जिसके अनुसार राज्य महिलाओं की सुरक्षा, रोज़गार, विकास के लिए और उत्पीड़न के विरुद्ध विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 39 (ड्ड) निर्देशित करता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन के उपयोग का अधिकार है।

संविधान निर्माण में इसके मूल में जो अधिकार स्त्री समाज को बलवती करने के लिए दिए गए थे, समय के अनुसार उनमें 50 से अधिक तब्दीलियां लाई गई हैं। बदलते समय के साथ महिलाओं के प्रति अपराध करने के तरीकों में भी बदलाव आया है और साथ ही महिलाओं ने कई जगह स्वयं को सिद्ध भी किया है। इन दोनों स्थितियों में स्त्रियों को और अधिक क़ानूनी सुरक्षा और क़ानूनी अधिकार देने की जरुरत है। अनेक नये विधेयक और मौजूद कानूनों में तब्दीली लाकर महिलाओं के हितों को और अधिक सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

अनैतिक व्यापार निषेध कानून, 1956 के अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरूष या बच्चों की खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यापार (इम्मोरल ट्रैफिकिंग) की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकना है। यह वेश्यावृत्ति के अनैतिक पहलुओं पर अंकुश लगाता है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 महिलाओं को दहेज़ के कारण होने वाली हिंसा, प्रताड़ना और हत्या जैसे अपराध से सुरक्षा देता है। इसके सेक्शन 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसमें 15 हजार तक के जुर्माने और 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। सेक्शन 4 कहता है कि दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। 1984 और 1986 में इसे संशोधित किया गया और कड़े कानून बनाये गए।

मातृत्व लाभ कानून, 1861 मातृत्व को प्राप्त कामकाजी महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। इसके अनुसार गर्भावस्था में और इसके तुरंत बाद कामकाजी महिलाओं को %पेड लीव% देने की बात कही गई है। अवकाश के दौरान 12 हफ़्तों के पूरे वेतन को देने से इसकी शुरआत की गई जो 2017 में 26 हफ़्तों तक की कर दी गई और अब नीति आयोग ने इसे पूरे 9 महीने करने की सिफारिश की है।

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 तलाक का अधिकार महिलाओं को भी देता है। तलाक के बाद उनके गुजारे-भत्ते की परिचर्चा करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के तहत एक ही तरह के काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को मेहनताना भी एक जैसा ही मिलना चाहिए। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम 1986, विज्ञापन या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है।

इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992, महिला सुरक्षा कानून 2016, पोक्सो एक्ट 2012, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, सती आयोग (निवारण) अधिनियम 1987, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 आदि कुछ कानून बनाये गए जो स्त्रियों की शुचिता, बराबरी के अधिकार, सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करते हैं।

अभी हाल के परिवर्तनों की चर्चा करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन इसी पुरानी संसद की लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सुधार की दृष्टि से तीन नये विधेयक पेश किये थे। इन विधेयकों ने नारी सुरक्षा को एक नया आयाम दिया। प्रस्तावित कानून में पहचान छुपाकर विवाह करने पर धारा 69 के अनुसार 10 साल की सज़ा और जुर्माना का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संहिता में धारा 70 डी के तहत नाबालिग से गैंग रेप करने की स्थिति में मौत तक की सजा तय की गई है। अब जबकि नये संसद भवन में प्रवेश हो गया है तब पुराने भवन में अधूरा रह गया काम नये भवन के विशेष सत्र में पूरा किया जा रहा है। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश हो चुका है जिसके तहत संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह नये संसद भवन में महिलाओं के लिए शुभ शुरुआत होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि पुराने संसद भवन में संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने से लेकर संसद की हाल तक चली कार्रवाई ने महिला अधिकारों की जो पटकथा लिखी है, नये संसद भवन में वह क्रम निरंतर जारी रहेगा।

हड्डियों के लिए खतरनाक स्मोकिंग, हो सकती हैं बीमारियां

धूम्रपान आपके स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है. इसके कारण हृदय रोग, स्ट्रोक, सांस संबंधी रोग, फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग आपकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. बता दें कि, धूम्रपान मानव शरीर के हर ऊतक को प्रभावित करता है. यह बोन डेंसिटी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको चलने, घूमने-फिरने में तक में मुश्किल आ सकती है. यह ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी के फ्रैक्चर के विकास की संभावना को बढ़ाता है और फ्रैक्चर को ठीक करने में देरी

स्मोकिंग ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को बढ़ाता है क्योंकि यह आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है. इसके परिणामस्वरूप आपकी हड्डियों को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है. यह आपके शरीर की कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता को भी कम कर देता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है. यह उस दर को तेज करता है जिस पर एस्ट्रोजेन, एक हार्मोन जो हड्डियों की सुरक्षा में सहायता करता है, टूट जाता है. इसके अलावा, हड्डियों (ऑस्टियोब्लास्ट्स) बनाने वाली कोशिकाओं का उत्पादन कम होता है.

मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर प्रभाव- धूम्रपान आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे बीमारी और चोट का खतरा बढ़ जाता है. जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनमें धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कंधे के फटने, चोट लगने, दर्दनाक चोटों, मोच और संधिशोथ होने का अधिक खतरा होता है.

घाव भरने की प्रक्रिया में बाधा- धूम्रपान घाव भरने की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे फ्रैक्चर. फ्रैक्चर का इलाज करने में अधिक समय लगता है क्योंकि सिगरेट में निकोटीन हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को बाधित करता है.

हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं का निर्माण, जो उपचार के लिए महत्वपूर्ण हैं, निकोटिन द्वारा धीमा हो जाता है. इसके अलावा, यह ऊतकों को रक्त की आपूर्ति कम होने के कारण सर्जरी के बाद जटिलताएं पैदा करता है.

गठिया- जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी बीमारी होने का खतरा अधिक होता है. इसके अलावा, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को और भी खराब कर सकता है और आपके जोड़ों में गंभीर दर्द और क्षति का कारण बन सकता है. इसके अलावा, यह रुमेटीइड गठिया के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के प्रभाव को भी कम कर सकता है.

पीठ में दर्द- धूम्रपान का एक और दुष्प्रभाव यह है कि यह आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द पैदा करता है. यह आपके स्पाइनल डिस्क में रक्त के प्रवाह और पोषक तत्वों के कम होने के कारण हो सकता है. जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें पुरानी पीठ दर्द होने का खतरा होता है.

हड्डियों की सेहत को सुधारने के उपाय

- **स्वस्थ आहार**- आपको एक स्वस्थ आहार बनाए रखना चाहिए और अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए.
- **सक्रिय रहें**- आपको एक गतिहीन जीवन शैली से बचना चाहिए और व्यायाम और खेल जैसी शारीरिक गतिविधियों में खुद को शामिल करना चाहिए. हालांकि, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको अपने व्यायाम की दिनचर्या के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- **शराब से परहेज करें** शराब आपके शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने से रोक सकती है, जिससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा, इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से आपका संतुलन बिगड़ने से आपके गिरने और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ सकता है.
- **धूम्रपान छोड़ें**- धूम्रपान छोड़ कर आप कई हेल्थ प्रॉब्लम के जोखिम को कम कर सकते हैं. यह आपके शरीर को स्वस्थ रहने और कुशलतापूर्वक कार्य करने में मदद कर सकता है. टूटी हुई हड्डियों से उबरना कठिन हो सकता है, और धूम्रपान करने वालों के लिए इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है.

काउंसलिंग और सही उपचार हो सकता है ड्रग एडिक्शन छुड़वाने में मददगार

अक्सर कुछ लोग नहीं चाहते हुए भी नशे के शिकार हो जाते हैं। कभी-कभार जानकारी के अभाव में भी दवा समझकर नशा करने लगते हैं। नशे का शिकार आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। जब हमें इस बात की जानकारी मिलती है, तो दुःख होता है। हमें सिर्फ इस विषय पर गहन चिन्तन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके प्रति जागरूक होकर कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए।

नशा रोधी दिवस- इन्टरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रेफिकिंग या वर्ल्ड ड्रग डे या नशा रोधी दिवस हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का लक्ष्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से विश्व को मुक्त करना और सहयोग प्राप्त करना है।

इस वर्ष की थीम है- लोगों की भलाई के लिए इसके स्टिग्मा और भेदभाव को रोकें और रोकथाम करें।

नशे के शिकार व्यक्ति के साथ प्रभावी बातचीत- अल्फा हीलिंग सेंटर के चीफ ग्रोथ ऑफिसर अतुल वाया के अनुसार, 'अक्सर जो लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, वे इसकी एडिक्शन को स्वीकार नहीं करना चाहते। नशीली दवाओं या शराब की लत को छुड़ाने के लिए वे मदद भी नहीं मांगना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने प्रियजन की मदद करें। नशे के शिकार व्यक्ति के साथ वे प्रभावी ढंग से बात करें और उन्हें इसके बुरे प्रभावों के बारे में समझाएं। उन्हें हेल्थकेयर प्रोफेशनल की मदद लेने के लिए राजी करें। यह कार्य अपने-आप में एक चुनौती है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यह व्यक्ति के लिए सकारात्मक और जीवन बदलने वाले परिणाम ला सकती है।'

क्या है ड्रग एडिक्शन- ड्रग एडिक्शन या नशा क्रोनिक और बार-बार होने वाला विकार है, जो नशीली दवाओं के लगातार प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव है। इसे मस्तिष्क विकार माना जाता है। इसके कारण ब्रेन सर्किट में फंक्शनल चेंज हो जाते हैं। इसके कारण तनाव, डिप्रेशन और सेल्फ कंट्रोल नहीं रहना हो जाता है।

समझिए ड्रग एब्यूज- अवैध दवाओं का उपयोग ड्रग एब्यूज कहलाता है। इसमें अन्य उद्देश्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रेस्क्रिप्शन या ओवर-द-काउंटर दवाओं का उपयोग किया जाता है। नशीली दवाओं के कारण सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और जॉब संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

शिक्षित करना-अतुल वाया कहते हैं, 'सबसे पहले समस्या को स्वीकार कर उस पर कार्यवाही करना जरूरी बन जाता है। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को सबसे पहले समस्या के परिणामों को बताना जरूरी है। नशे के दुष्परिणाम को बताने के लिए व्यक्ति पर लगाम लगाना भी जरूरी है। एडिक्ट व्यक्ति को अपनी समस्या के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। समस्या के निदान को तलाशने की कोशिश करें।

व्यक्तिगत उपचार-हर व्यक्ति के ठीक होने का ढंग अलग-अलग होता है। पुनरुद्धार केंद्र व्यक्तिपरक उपचार योजना बनाते हैं। ये उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार होती हैं। अतुल वाया के अनुसार, यदि समस्या गंभीर हो तो पुनर्वास केंद्र की मदद मांगना जरूरी हो जाता है। व्यसन से जूझ रहे किसी व्यक्ति को पेशेवर मदद की जरूरत सबसे अधिक होती है।

साक्ष्य आधारित उपचार- पुनर्वास केंद्र व्यक्तियों को नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार बदलने में मदद करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी (डीबीटी) और प्रेरणादायक बातचीत जैसे साक्ष्य-आधारित उपचारों का उपयोग करते हैं।

परिवार और मित्रों का सहयोग- पुनर्वास केंद्र के ग्रुप थेरेपी सेशंस में नशे से जूझ और उबरने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती है। इससे उन्हें समान अनुभवों से गुजरने वाले अन्य लोगों से जुड़ने का अवसर मिल पाता है। इनके अलावा, परिवार और मित्रों का सहयोग सबसे अधिक मिलना चाहिए, जिनसे वे अपनी बात शेयर कर सकें।

आफ्टरकेयर प्लानिंग- व्यक्ति को रिकवर होने में लंबा समय लगता है। इसलिए उन्हें लगातार देखभाल और मानसिक संबल की जरूरत पड़ती है। पुनर्वास केंद्र में आफ्टरकेयर योजनाएं भी होती हैं। ये उन्हें फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मजबूती देने में मदद करते हैं।

हॉर्मोन संतुलित करने के लिए डाइट में शामिल करें ये 6 खाद्य पदार्थ

हॉर्मोन असंतुलन हम अक्सर तनाव, नींद की समस्या, पाचन की गडबडी, चयापचय, स्किन और मस्तिष्क स्वास्थ्य समस्या का सामना करते रहते हैं। पर हम यह समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे हार्मोन जिम्मेदार हो सकता है। यह हॉर्मोन असंतुलन भोजन के कारण हो सकता है। कई खाद्य पदार्थ इस असंतुलन को बढ़ाते हैं। बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें आहार में शामिल करने से हॉर्मोन असंतुलन खत्म हो जाता है। फूड हॉर्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं।

हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, सबसे पहले आहार से उन खाद्य पदार्थों को निकलना चाहिए, जो हार्मोनल असंतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, परिष्कृत शर्करा, शराब, कैफीन और संतृप्त पशु वसा शामिल हैं। इन सभी में मौजूद प्रोसेस्ड न्यूट्रीएंट शरीर को लाभ पहुंचाने की बजाय हानि करते हैं। यह शरीर द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत आंत से ही होती है।

हार्मोनल संतुलन से आती है मजबूती- हार्वर्ड हेल्थ में प्रकाशित शोध आलेख के अनुसार, खाद्य पदार्थ ओवरआल हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करने में मदद करते हैं। इससे मूड स्विंग में कमी आती है। इससे अवसाद, चिंता, थकान और चिड़चिड़ापन के लक्षणों में कमी आती है। हार्मोनल संतुलन से मानसिक तौर पर व्यक्ति मजबूत होता है। फोकस और शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। हार्मोन संतुलन से मुंहासे, बालों का झड़ना, रात को पसीना आना और गर्मी लगना आदि जैसे लक्षण कम हो सकते हैं।

गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जी-जर्नल ऑफ़ फूड साइंस के अनुसार, गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जी सूजन से लड़ने में मदद करती है। यह हमारे कोर्टिसोल स्तर को कम करती हैं, जो तनाव बढ़ाते हैं। इससे शरीर की कोशिकाओं की टूट-फूट कम हो जाती है। हरी सब्जियां शरीर में आयरन कंटेंट को बढ़ाती हैं। यह ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाती हैं। यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती हैं।

ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ- जर्नल ऑफ़ फूड साइंस के अनुसार, अखरोट, सैल्मन, ऑलिव आयल, अलसी के बीज, चिया सीड्स आदि को अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड सेलुलर झिल्ली की रक्षा करने के अलावा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, याददाश्त में सुधार करने, हमारे मूड को बेहतर बनाने और सूजन को कम करने में मदद करता है।

हल्दी- जर्नल ऑफ़ फूड साइंस के अनुसार, सबसे प्रसिद्ध एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंटों में से एक है हल्दी। हल्दी के भीतर सक्रिय घटक करक्यूमिन है, जो हार्मोनल स्थितियों, विशेष रूप से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए बहुत मददगार हो सकता है। एस्ट्रोजेन को खत्म करने के लिए चयापचय में लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हल्दी इस तंत्र के माध्यम से हार्मोन रेगुलेशन पर प्रभाव डाल सकती है। यह शरीर को प्राकृतिक रूप से संतुलित हार्मोन स्तर प्राप्त करने में मदद करता है।

एवोकाडो- हार्वर्ड हेल्थ के शोध आलेख बताते हैं कि एवोकैडो में बीटा-सिटोस्टेरॉल तत्व मौजूद होता है। यह स्वाभाविक रूप से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। ये स्वाभाविक रूप से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं और हॉर्मोन संतुलित करते हैं।

नारियल, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज- हार्वर्ड हेल्थ के शोध आलेख बताते हैं कि नारियल, सूरजमुखी के बीज, और कद्दू के बीज में एमसीटी या मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद होते हैं।

रोजाना 1 कली लहसुन से कम हो जाता है हार्ट अटैक का खतरा

लहसुन का उपयोग हृदय रोग सहित विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में सदियों से किया जाता रहा है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जो इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार है। शोध से पता चला है कि लहसुन कई तरह से हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि लहसुन की अधिक मात्रा का सेवन करने से आपको पेट में गैस, बदहजमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लहसुन के उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से विशेष सलाह लें और अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन न करें। इस लेख में हम लहसुन के उपयोग से हार्ट पेशेंट को कैसे फायदा मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे।

हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है- लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व हमारे शरीर के रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इससे हमारे दिल की सेहत मजबूत होती है और हमारे दिल का जोखिम कम होता है। इसलिए, हार्ट पेशेंट के लिए लहसुन एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।

रक्तचाप को नियंत्रित करता है

लहसुन में मौजूद अलिस्टीन नामक तत्व हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार होता है। इससे हमारे शरीर का रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हमारे दिल को कोई जटिलता नहीं होती है।

कोलेस्ट्रॉल को कम करता है

लहसुन में मौजूद अल्युमिन नामक तत्व हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। इससे हमारे शरीर में जमा हुए विषैले पदार्थ कम होते हैं और हमारे दिल को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए, हार्ट पेशेंट के लिए लहसुन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है।

थायराइड को नियंत्रित करता है

लहसुन में मौजूद सेलेनियम नामक तत्व हमारी थायराइड को नियंत्रित करने में मददगार होता है। इससे हमारी थायराइड की सेहत मजबूत रहती है और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को भी फायदा होता है।

एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है

लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को नष्ट करते हैं। इससे हमारे शरीर की सेहत अच्छी रहती है और हमारे हार्ट को कोई जटिलता नहीं होती है।

क्या विटिलिगो या सफेद दाग का इलाज संभव है?

विटिलिगो (सफेद दाग) होने पर आपकी स्किन अपना रंग खोने लगती है और पिगमेंटेशन भी खोने लगती है। इससे आपकी स्किन पर कहीं कहीं सफेद दाग होने लगते हैं। यह दाग पूरी तरह से स्मूथ होते हैं और यह स्किन के किसी भी भाग में हो सकते हैं। शुरुआत में यह आपके हाथों, मुंह, माथे और पैरों पर होते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 1 प्रतिशत लोगों को यह स्थिति होती है। हालांकि इसका उपचार संभव है, आइए जानते हैं विटिलिगो के बारे में।

क्या है विटिलिगो

इसमें आपकी स्किन का रंग खोने लगता है और स्किन प्राकृतिक रंग से थोड़ी लाइट होने लगती है। अक्सर स्किन सफेद हो जाती है और ऐसा लगता है की कहीं कहीं आपकी स्किन पर सफेद दाग हो गए हैं। अगर जिन भागों पर यह दाग होते हैं वह एक सेंटीमीटर से छोटे होते हैं तो उन्हें मैक्यूल कहा जाता है और एक सेंटीमीटर से चौड़े होते हैं तो उन्हें पैच कहा जाता है।

लाइट थेरेपी- लाइट थेरेपी या फोटो थेरेपी का प्रयोग करके भी आपकी स्किन का पहले वाला रंग वापिस लाया जा सकता है।

डिपिगमेंटेशन थेरेपी- यह थेरेपी आपकी स्किन का प्राकृतिक रंग कम करके विटिलगो से प्रभावित क्षेत्र से स्किन का रंग मैच करने में मदद करती है।

सर्जरी- कई बार विटिलगो से प्रभावित लोगों को डॉक्टर सर्जरी करवाने की भी सलाह दे सकते हैं।

विटिलिगो के लक्षण- स्किन पर सफेद रंग के दाग हो जाना। शरीर पर बालों का सिल्वर, ग्रे या फिर सफेद हो जाना। हाथ, पैर, बाजू, मुंह, म्यूकस मेंब्रेन और जेनिटल पर यह लक्षण दिखना।

विटिलिगो का कारण- अगर आप किसी ऑटो इम्यून स्थिति से परेशान हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही हेल्दी सेल्स को फॉरेन सेल्स समझ कर उन पर अटैक करने लगता है तो इस वजह से भी यह दाग हो सकते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का जेनेटिक बदलाव आता है या फिर आपके डीएनए में बदलाव होता है तो भी यह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अगर ज्यादा ही परेशान रहते हैं तो अधिक स्ट्रेस के कारण आपकी सेल्स का पिगमेंट बदल सकता है।

क्या विटिलिगो का इलाज संभव है?- यह स्थिति आपके शरीर के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होती है इसलिए इसका इलाज जरूरी नहीं होता है। अगर विटिलिगो के कारण आपको शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो इसका इलाज संभव है और आपके डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिससे आपकी स्किन का पहले वाला पिगमेंट दोबारा से आ सके।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

23 सितंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नईदिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। दोपहर लगभग 1.30 बजे प्रधान मंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। अपराह्न लगभग 3.15 बजे, प्रधानमंत्री रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वह पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आधुनिक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। वाराणसी के गांजरी, राजातालाब में बनने वाला आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

चीन पर कांग्रेस के सवाल पर भड़के राजनाथ सिंह

नईदिल्ली। लोकसभा में जिस वक्त राजनाथ सिंह महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सांसदों को धन्यवाद दे रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कई बार बाधित करने की कोशिश की। अधीर रंजन ने राजनाथ से चीन पर सवाल करने की कोशिश की। एक-दो मौकों पर राजनाथ ने उन्हें टाला। हालांकि, जब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्या सरकार के पास लद्दाख में चीन से टकराव के मुद्दे पर चर्चा की हिम्मत है, तो राजनाथ बिफर गए। उन्होंने कहा, पूरी हिम्मत है... राजनाथ ने यह कई बार दोहराया भी। इसके बावजूद जब अधीर रंजन नहीं रुके, तो राजनाथ ने कहा, अधीर रंजन इतिहास में मत जाओ। चर्चा चीन पर भी होगी। इसके बाद अधीर रंजन ने कहा कि सरकार ने आश्वसान दिया था कि चीन पर चर्चा होगी, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। इस पर राजनाथ ने कहा, हमने सुन ली आपकी बात, अब हमारी भी सुन लो। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं चर्चा को तैयार हूं और सीना चौड़ा कर के चर्चा के लिए तैयार हूं।

लैंड फॉर जॉब मामले में फिर टली सुनवाई

नईदिल्ली। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित 17 लोग आरोपित हैं। गृह मंत्रालय से इस मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद गुरुवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन यह सुनवाई टल गई। वहीं इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 12 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई टलने से फिलहाल तेजस्वी यादव सहित अन्य को राहत मिली है। वहीं सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में दायर चार्ज शीट पर सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। अगर कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट को स्वीकार कर लिया और तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में उन्हें जमानत लेनी होगी।

सिर पर बैग उठाये रेलवे स्टेशन पर कुली बने राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और कुली की ड्रेस में नजर आएं। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस नेता ने कुलियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी बेहद अलग अंदाज में दिखाई दिए जहां उन्होंने कुली की तरह लाल शर्ट पहनकर हाथों में बैच लगाकर किसी यात्री के सामान को सिर पर उठाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, गुरुवार को राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचकर कुलियों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को लेकर बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने उस वक्त सभी को चौंका दिया जब उन्होंने खुद कुली बन सामान उठाया। राहुल गांधी का दौरा कुछ महीनों बाद हो रहा है जब कुछ कुलियों ने उनसे मिलने का आग्रह किया था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुली और ऑटो ड्राइवर काफी खुश नजर आए।

अक्तूबर में आएगी कांग्रेस की सूची : सचिन पायलट

जयपुर। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पालयट ने टोंक में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अक्तूबर में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। हम सब मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर सरकार बनाएंगे। इधर, पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, इसका निर्णय पार्टी करेगी। पायलट ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब मैंने पहले टोंक से चुनाव लड़ा था, तब आपने वोटों के बड़े अंतर से मुझे जिताया था। इस बार आपको उससे भी ज्यादा वोटों से जिताना है। सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वाहवाही लूटने के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक में नारी का विशेष योगदान : जेपी नड्डा

नईदिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस शुरू की और कोटा विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण विधेयक से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश चतुर्थी के अवसर पर हुई और कल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम निर्विघ्न पारित हुआ और मुझे विश्वास है कि आज राज्य सभा में भी यह बिना किसी बाधा के सर्वसम्मति से पास होगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिला आरक्षण का जो विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसे उन्होंने एक निर्णायक मोड़ दिया है।

नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के लिए पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी जब महिला सशक्तिकरण कहते हैं, तो वे हमेशा महिला नेतृत्व विकास की बात करते हैं। उन्होंने ज20 में भी दुनिया को बताया कि यह केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, यह महिला नेतृत्व वाला विकास है। भारत की इस सोच को उन्होंने दुनिया के सामने ज20 में भी रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान आर्थिक स्वायत्ता में हमेशा रहा है। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। वहीं, विधेयक पेश करते समय राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं...जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा। उन्होंने कहा कि मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह एक बड़ा कदम है।

राहुल गांधी पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कसा तंज

राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा। ट्यूटर से काम नहीं चलता है। एनजीओ को लेकर आ जाते हैं। वो आपको समझाते हैं और आप बोलकर निकल जाते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान सरकार पर सीधा हमला करते हुए पूछा था कि सरकार में कितने कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी है। इस सवाल पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि पहले वे ये बताएं 2004 से 2014 के बीच कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे। उन्होंने कहा, नेहरु कार्यकाल में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दो। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, अभी जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वे सभी 1992 से पहले के लोग हैं।

जेपी नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि आजाद भारत में 12 महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। कई देशों में महिलाओं ने वोटिंग राइट्स के लिए संघर्ष किया है। हमारे देश के पहले आम चुनाव में यह अधिकार महिलाओं को मिल गया था। यहां तक कि हमारे देश को कई दूसरे के मुकाबले पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी।

राज्य सभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बयान पर भड़के जगदीप धनखड़

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अपमान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नई संसद के उद्घाटन में मौजूद नहीं थे। धनखड़ ने कहा, हम कमियों पर समझौता नहीं कर सकते। हम दूसरों की अज्ञानता का व्यापार नहीं कर सकते। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को देश में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अथवा चेयरमैन का पद अपेक्षानुसार उनके स्तर का ही रखना होगा और वही किया गया। और पिछले तीन दिनों में भी आपने यही देखा है।

जगदीप धनखड़ ने प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य के रूप में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपना होमवर्क अवश्य करें। पता लगाना। जब आप राष्ट्रपति को भी लाते हैं तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाता। उन्होंने कहा कि संविधान पढ़ें और आप पाएंगे कि भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करेंगे, यही संविधान में मूल निर्देश था। और (पहला) संशोधन था, साल में एक बार। राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। धनखड़ ने संसद के चल रहे विशेष सत्र में वेणुगोपाल को जवाब दिया। गौरतलब है कि विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले दिन में, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक महिला और उच्च पद संभालने वाले आदिवासी समुदाय के पहले व्यक्ति को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा शुरू करते हुए, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना चाहता है रंजन ने यह भी सवाल किया कि 2014 में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में इसका वादा करने के बावजूद भाजपा को विधेयक लाने में साढ़े नौ साल क्यों लग गए।

महिला आरक्षण के लिए जरूरी है जनगणना और परिसीमन

नईदिल्ली। विपक्षी नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक को अगली जनगणना और परिसीमन से जोड़ने के लिए सरकार की आलोचना की। विपक्ष का दावा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा देने वाले ऐतिहासिक कानून के कार्यान्वयन में देरी होगी। देश भर में सभी क्षेत्रों के लोगों ने मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन कार्यान्वयन में देरी पर चिंता भी व्यक्त की। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार चुनाव खत्म होते ही जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। जनगणना और परिसीमन की कवायद उन लोगों के लंबे समय से लंबित सपने को साकार करने की राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी जो इस कानून के लिए आवाज उठा रहे थे।

संविधान (128वां संशोधन) विधेयक के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक के कानून बनने के बाद आयोजित जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन अभ्यास या निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद ही प्रभावी होगा। संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद इसे कानून बनने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी।

जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

लोकसभा या विधानसभा के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र की जनसांख्यिकी स्थिर नहीं रहती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए, जनसंख्या की प्रकृति और संख्या को समझने के लिए जनगणना आवश्यक है ताकि सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन से प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य प्राप्त हो सकें। 2021 की जनगणना प्रक्रिया को सरकार ने ष्टह्लङ्कह्लष्ठ-19 महामारी के मद्देनजर स्थगित कर दिया था। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को हकीकत में बदलने के लिए सरकार को तेजी से काम करना होगा।

परिसीमन क्यों महत्वपूर्ण है?

चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार कि परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्च-शक्ति निकाय को सौंपा गया है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। समय की एक निश्चित अवधि के भीतर परिसीमन आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने से निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में व्यापक विसंगतियां हो जाएंगी, जिनमें से सबसे बड़े में लाखों से अधिक मतदाता हैं, और सबसे छोटा एक लाख से भी कम। परिसीमन एक राज्य के सांसदों की संख्या और एक राज्य में विधान सभा के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित करता है। 2002 के परिसीमन में, भारत में कुल विधायकों की संख्या 3,997 से बढ़कर 4,123 हो गई। परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत भारत में चार बार परिसीमन हुआ 1952, 1962, 1972 और 2002 के तहत भारत में चार बार परिसीमन हुआ - 1952, 1962, 1972 और 2002।

खेल
प्रमुख समाचार

बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर भारतीय महिला टीम की सेमीफाइनल में एंट्री

हांगझोऊ। शेफाली वर्मा ने मलेशिया के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ते हुए 39 गेंद में 67 रन बनाये लेकिन एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा का क्वार्टर फाइनल बारिश से रद्द हो गया। भारत को बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। मैच 15 ओवर प्रति टीम कर दिया गया था।

भारत ने दो विकेट पर 173 रन बना लिये थे। कप्तान स्मृति मंधाना ने 16 गेंद में 27 और जेमिमा रौड्रिग्ज ने 29 गेंद में 47 रन बनाये। रिचा घोष ने सात गेंद में 21 रन का योगदान दिया। मलेशिया के लिये सौ रन से आगे बढना भी मुश्किल लक्ष्य था। डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर संशोधित लक्ष्य 177 रन का मिला। मलेशिया ने दो गेंद ही खेली थी कि भारी बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा।

टूर्नामेंट में भारत शीर्ष रैंकिंग वाली एशियाई टीम है जिसके आधार पर उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला। मलेशिया की कप्तान विनिफ्रेड दुराइसिंघम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था लेकिन उनके क्षेत्ररक्षकों ने निराश किया और कई कैच टपकाये। गेंदबाज भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके। भारत की सलामी जोड़ी ने पावरप्ले में 59 रन बनाये। स्पिनर माहिरा इज्जाजी इस्माइल ने मंधाना को आउट किया।

शेफाली ने दूसरे छोर से आक्रामक खेलना जारी रखा और अपनी पारी में पांच छक्के तथा चार चौके जड़े। जेमिमा ने भी अपनी पारी में छह चौके लगाये और दूसरे विकेट के लिये शेफाली के साथ 86 रन जोड़े।उन्हें मास एलिसा ने पगबाधा आउट किया। रिचा ने 15वें ओवर में चार चौके लगाये जिससे भारत ने 170 के पार का स्कोर बनाया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 571 अंक गिरकर बंद निफ्टी 19,750 के नीचे आया

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई और बीएसई सेंसेक्स 571 अंक का गोता लगातार बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचा बना रहने के संकेतों के चलते वैश्विक बाजारों में गिरावट के रुख का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। साथ ही ऑटो और आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से भी बाजार में गिरावट आई। आज के कारोबार में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 570.60 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट लेकर 66,230.24 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 66,608.67 अंक पर खुला था और पूरे दिन इसके आगे नहीं बढ़ सका। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 66,800.84 अंक पर बंद हुआ था।

पियाजियो प्रीमियम टू व्हीलर सेगमेंट में करेगी विस्तार

नईदिल्ली। इटली के पियाजियो समूह का लक्ष्य भारत में प्रीमियम टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है, क्योंकि कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा संपन्न विकल्प तलाश रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी पियाजियो व्हीकल्स के जरिए भारत में मौजूद है। उसने अप्रिलिया आरएस 457 का अनावरण करके बढ़ते मध्यम आकार के मोटरसाइकिल खंड में प्रवेश किया। कंपनी पहले से ही देश में अप्रिलिया और वेस्पा ब्रांड के तहत पांच प्रीमियम स्कूटर मॉडल बेचती है। पियाजियो व्हीकल्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डिएगो ग्राफी ने कहा, 'हमने देखा है कि अधिक से अधिक ग्राहक आवाजाही के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ और संतोषजनक चाहते हैं।

टीवीएस मोटर ने किया भारत की पहली टू-व्हीलर्स इलेक्ट्रिक रेसिंग चैंपियनशिप का ऐलान

नईदिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी ने गुरुवार को टिकाऊ वाहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए भारत की पहली इलेक्ट्रिक दोपहिया रेसिंग चैंपियनशिप शुरू करने का ऐलान किया। टीवीएस रेसिंग इलेक्ट्रिक वन मेक चैंपियनशिप के साथ ही इलेक्ट्रिक अपाचे आरटीई भी अपना डेब्यू 29 सितंबर को करेगी। टीवीएस रेसिंग इलेक्ट्रिक वन मेक चैंपियनशिप इलेक्ट्रिक टीवीएस अपाचे आरटीई रेस मोटरसाइकिलों से रेसिंग के लिए एक एक्सक्ल्यूजिव फॉरमैट है जिसे पूरी तरह से चैंपियनशिप के लिए डेवलप किया गया है। टीवीएस मोटर क्लीन फ्यूचर के लिए इनोवेशन और सस्टेनेबल सॉल्यूशन्स के माध्यम से मोबिलिटी को बदलने के क्षेत्र में आगे रही है, और टीवीएस रेसिंग के साथ भारत में मोटरस्पोर्ट्स का भी नेतृत्व किया है।

कम ब्याज दरों की वजह से घटी बचत

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो दर स्थिर रखी थी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया था। जिसके चलते लोगों ने घरेलू बचत करने की बजाय संपत्तियों में निवेश किया है। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिसर्च के अनुसार, बीते दो सालों में रिटेल क्रेडिट का 55 फीसदी हिस्सा घर खरीदने, उच्च शिक्षा और वाहनों की खरीद में इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि रिजर्व बैंक डाटा ऑन हाउसहोल्ड एसेट एंड लायबिलिटीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लोगों की घरेलू बचत में गिरावट आई है और यह 50 साल में सबसे निचले स्तर पर है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घरेलू बचत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल जीडीपी की सिर्फ 5.1 प्रतिशत रह गई है जबकि 2020-21 में यह 11.5 प्रतिशत थी और कोरोना महामारी से पहले यह 7.6 प्रतिशत थी।

ऐसे बनेंगे आर्थिक महाशक्ति, चीन से सबक हासिल कर सकता है भारत

संतोष मेहरोत्रा

बीती सदी के आठवें दशक के प्रारंभ में भारत को जो जनसांख्यिकीय लाभांश मिलना शुरू हुआ था, वह 2030 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। चीन का जनसांख्यिकीय लाभांश करीब एक दशक पहले ही खत्म हो गया था, पर उसने इसका पूरा लाभ उठाया और तीन दशकों तक जीडीपी में नौ से 10 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की।

वर्ष 1980 तक भारत और चीन प्रति व्यक्ति आय के समान स्तर पर थे, पर अब, पीपीपी के मानक में चीन की प्रति व्यक्ति आय 18,000 डॉलर है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 7,000 डॉलर ही है। ऐसे में, देश को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करें कि जीडीपी लगातार कम से कम आठ फीसदी सालाना की दर से तब तक बढ़े, जब तक इसका लाभांश समाप्त न हो जाए, ताकि इसकी युवा आबादी के लिए पर्याप्त गैर-कृषि रोजगार पैदा हो सके। वर्ष 2004-14 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी, जबकि वर्ष 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था।

वर्ष 2004-05 और 2011-12 के दौरान अर्थव्यवस्था हर साल 75 लाख नई गैर-कृषि नौकरियां पैदा कर रही थी, इसीलिए युवा और कुल बेरोजगारी कम थी। इसने अभूतपूर्व पैमाने पर श्रमिकों को कृषि से बाहर निकाला, जो चीन और अब औद्योगिकीकृत देशों में पहले हुए संरचनात्मक परिवर्तन की एक विशेषता है। 2004 से 2014 के दौरान गैर-कृषि रोजगार सृजन से ग्रामीण श्रम बाजार में सख्ती आई, जिससे खुले बाजार में मजदूरी बढ़ी। गरीबी कम हुई और 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। पर 2013-2019 के बीच सृजित

गैर-कृषि नौकरियों की संख्या 75 लाख सालाना से गिरकर 29 लाख रह गई। 2015 के बाद से कुल विनिर्माण नौकरियों में पूर्ण रूप से गिरावट आई। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान, जो 1992 से 2015 तक 17 फीसदी पर स्थिर था, उसके बाद 13 फीसदी तक गिर गया, हालांकि 2022-23 में यह फिर बढ़कर 17 फीसदी हो गया।

वर्ष 2014 से 2022 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी होकर 5.7 फीसदी सालाना क्यों हो गई? इसका मुख्य कारण आर्थिक नीति प्रबंधन है। सबसे पहले सरकार ने 2016 में 86 फीसदी करेंसी का विमुद्रीकरण कर दिया। नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था में इसने अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को संकट में डाल दिया। फिर जिस एमएसएमई क्षेत्र में सबसे अधिक गैर-कृषि नौकरियां उत्पन्न होती थीं, विमुद्रीकरण के छह महीने बाद उसे एक और झटका लगा, जब जीएसटी लागू किया गया, जिसमें 17 राज्यों के वैट और अन्य अप्रत्यक्ष कर शामिल हो गए। खराब योजना के कारण जीएसटी ने एमएसएमई को और अधिक नुकसान पहुंचाया। नतीजतन, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर करीब तीन वर्षों तक धीमी होकर चार फीसदी पर आ गई। मार्च, 2020 में जब देश में कोविड के 600 मामले थे, तब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं। उसने छह करोड़ श्रमिकों को शहरों से गांवों में भेज दिया, जिससे कृषि पर अत्यधिक बोझ पड़ा और उसका रोजगार में हिस्सा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया। खुली बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जो 45 वर्षों में सबसे अधिक है। जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिए लाखों लोगों को कृषि से बाहर निकालने की जरूरत है। गैर-कृषि नौकरियों की जरूरत वाले युवाओं में लड़कियों पर फोकस करना चाहिए, जिन्होंने 2015 तक माध्यमिक शिक्षा में 80 फीसदी सकल नामांकन दर हासिल कर ली थी। कुल मिलाकर, देश को हर साल कम से कम 1-1.2 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत है। भारत ने 2000-2012 में सालाना 75 लाख गैर-कृषि नौकरियां पैदा की हैं और फिर से ऐसा हो सकता है। पर इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद में निवेश को 35 फीसदी तक बढ़ाने और विकास दर को आठ फीसदी तक ले जाने की जरूरत है।

भूपेश के गढ़ में पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा

पाटन में हुई सभा, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

दुर्ग। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज दुर्ग पहुंची. भाजपा की परिवर्तन यात्रा उतई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंची, जहां सर्किट हाउस मैदान में सभा हुई, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. पाटन की सभा में भाजपा नेता और पद्मश्री अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर गीत कविता के माध्यम से निशाना साधा.

भाजपा की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास,, पाटन से भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, भाजपा नेता अनुज शर्मा मंच पर मौजूद रहे. वहीं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के उतई में आयोजित सभा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विजय बघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व मंत्री रमशीला साहू शामिल हुए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने परिवर्तन यात्रा की सभा के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, सीएम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का नाम लेते हैं, ये कैसे बना. 15वें वित्त आयोग का पैसा कहां गया. सांसद विजय बघेल ने पैसा देने का काम किया. मनरेगा , कैम्पा का पैसा विजय बघेल जी ने लाया. सीएम ने लूटकर खाने का काम किया. केंद्र ने कोरोना काल में 15 किलो चावल, राशन दुकानों में भेजा, लेकिन पांच किलो चावल सरकार खा गई. ये ईडी आईटी को गाली देते हैं. न्यायपालिका का विरोध करें. सोनवानी को पीएससी का चेयरमैन बनाया, जिसने अपने ही परिवार के लोगों को अधिकारी बना लिया.

मलकीत सिंह हत्याकांड सीबीआई जांच की मांग करे

भाजपा के परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज खुर्सीपार पहुँचे। जहां स्व. मलकीत सिंह के पीड़ित परिवार से भेंट कर ढांढ़स बंधवाया। रघुवर दास ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर यहां किसी की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। एक होनहार युवक मलकीत सिंह की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई। यह घटना दु:खद है विश्वास नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ के हालात इतने खराब हो गए। मुलाकात के दौरान परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में लीपापोती का काम किया जा रहा है रघुवर दास ने कहा कि जांच की मांग परिवार के द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि इस घटना पर सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। रघुवर दास में कहा कि पीड़ित परिवार और क्षेत्र की जनता को पुलिस के कार्रवाई पर भरोसा नही है। परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन मामले में बार बार दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार से भेंट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास ने कहा कि इस अन्याय और हत्या के खिलाफ परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरा न्याय दिलाने का तक संघर्ष करेगी, हर संभव प्रयत्न पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है।

एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। चुनाव को लेकर केंद्र के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। 21 सितंबर को यानी आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दुर्ग दौरे पर हैं वे भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हुए । तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन में चुनावी बिगुल फूंकने दौरे पर आई। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी 25 सितंबर को तखतपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे।

उच्च न्यायालय ने पीएससी घोटाले का पर्दाफाश किया: कंवर

रायपुर। पूर्व मंत्री एवं विधायक ननकीराम कवंर ने कहा है कि पीएससी घोटाले के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भूपेश सरकार का काला चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे है। 2021 की लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम में जिस प्रकार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सचिव प्रदेश के अन्य उच्च अधिकारी एवं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के परिजन बड़ी संख्या में नियुक्त हुए उससे बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय का पर्दापाश हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले में माननीय न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी की है, न्यायालय ने सच सबके सामने ला दिया है। उन्हें व सभी युवा उम्मीदवारों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। श्री कवर ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग माननीय न्यायालय से की है।

पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब परीक्षा परिणाम में अधिकारी और नेताओं के बच्चों के नाम सामने आए थे तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे कि अधिकारी या नेता के बच्चे परीक्षा में चयनित क्यों नहीं हो सकता? पर न्यायालय ने एक साथ 18 अधिकारी व नेताओं के परिजनों की भर्ती पर प्रश्न खड़ाकर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सोनवानी के 6-6 रिश्तेदार एक साथ कैसे सिलेक्ट हो सकते है? उन्होंने बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से लोक सेवा आयोग में हो रही अनियमितता, धांधली और भाई-भतीजावाद का भांडा फूटने के बाद आयोग इसकी जांच करने के बजाय सबूत को नष्ट करने की कोशिश में लगते है। श्री कंवर ने कोर्ट में प्रस्तुत किए गए अपने हलफनामे में इस बात का उल्लेख किया है कि पीएससी के परिणाम आने के बाद जब विवाद हुआ तब आयोग ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के दस्तावेज जिसमें ओएमआर शीट व उत्तर पुस्तिकाएं शामिल है को रद्दी में बेचने की निविदा जारी कर दी थी।श्री कंवर ने कहा कि पीएससी में हो रही गड़बड़ियों में जांच करने में प्रदेश की जांच एजेसियां सक्षम नहीं है और प्रदेश सरकार की इच्छाशक्ति भी नहीं है।

चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक

रायपुर। संस्कृति विभाग द्वारा लौह नगरी रायगढ़ में प्रतिवर्ष की तरह आयोजित इस वर्ष की चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। चक्रधर समारोह में स्थानीय स्कूली छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक छटा बिखेरा। विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्कृति को नृत्य के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति दी। समारोह में राउत नाचा से लेकर सुआ, ददरिया, कर्मा जैसे विभिन्न स्थानीय सांस्कृतिक नृत्यों के साथ देश के विभिन्न राज्यों के ओड़िशी, गुजराती बिहू जैसे सांस्कृतिक नृत्यों की झलक भी देखने को मिली। स्कूली बच्चों के मनमोहक प्रस्तुति का शहरवासियों ने आनंद उठाया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उल्लेखनीय है कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा की पहल पर इस वर्ष चक्रधर समारोह में स्थानीय कलाकारों के साथ ही स्कूली एवं नवोदित कलाकारों को बड़ी संख्या में अवसर दिया गया हैं।समारोह में एमएसपी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत भारत मां की जय बोलव रे, छत्तीसगढ़ की जय बोलव, तिरंगा झंडा लहराए जावथे, जन-गण-मंगल के धुन गावथे पर छत्तीसगढ़ी नृत्य के साथ मनमोहक प्रस्तुति दी। इसी प्रकार न्यू होराइजन स्कूल के बच्चों ने झुलना मा झूले... छत्तीसगढ़ी लोक गीत पर कर्मा नृत्य की जबरदस्त प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की इस कड़ी में जिंदल आदर्श ग्राम्य भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों ने ओडिशा की संबलपुरी नृत्य से दर्शकों का दिल जीता।

नहीं आ रहे अमित शाह, तय कार्यक्रम किया गया रद्द

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा टल गया है। 22 सितंबर को अमित शाह रायपुर आने वाले थे। गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह का दौरा रद्द होने की पुष्टि की गई है। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वह स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर से इस बैठक के लिए नया शेड्यूल तैयार किया जाएगा। अमित शाह दिल्ली में होने वाले कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं जिसके बाद वह इस बैठक को समय देंगे।

2 सितंबर को आए थे शाह

2 सितंबर को भी अमित शाह रायपुर आए थे। भाजपा के आरोप पत्र लॉन्च कार्यक्रम में शाह ने 21 सौ करोड़ के शराब घोटाले को केवल टिप बताया था। भ्रष्टाचार मामले में प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरा था। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार इससे कहीं ज्यादा का है। आरोप पत्र में भाजपा ने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के साथ ही सरकार की विफलताओं के मुद्दों पर फोकस किया है।

नाराजगी जता चुके हैं शाह

अमित शाह जुलाई में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक ले चुके हैं। तब खबर यह भी सामने आई थी कि शाह स्थानीय नेताओं की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। तब मिली फटकार के बाद अचानक स्थानीय नेताओं ने अभियानों की तेजी लाई और यह कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। मगर यह भी बड़ा सच है कि बहुत सी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, अमित शाह इसी पर रिव्यू करने पहुंचने वाले हैं।

छालीवुड कलाकारों की मांग मिनी थियेटर के साथ फिल्म हो टैक्स फ्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं चाहे वे थियेटर आर्टिस्ट हो या फिल्मों में काम करते हो उनमें कला की कोई कमी नहीं है लेकिन जब भी कोई बड़ा समारोह व सांस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो छालीवुड के कलाकारों को वह तवज्जो नहीं मिलता है तो बाहरी कलाकारों को दिया जाता है। इसके साथ ही यहां पर सिनेमाघरों की काफी कमी है इसको ध्यान में रखते हुए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी थियेटर खोलने की अनुमति राज्य सरकार अगर दे देती है तो छत्तीसगढ़ी में बनने वाली जितने भी फिल्में में वे अपनी लागत वसूल कर सकेंगे और इसके साथ सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। उक्त बातें शक्रवार को रिलीज हो रही छालीवुड फिल्म देख झन फंस जाबे के निर्देशक व फाईटर मास्टर बीरबल पानीग्राही, अभिनेता संदीप त्रिपाठी, काजल पांडेय व संध्या वर्मा ने कहीं।

बीरबल पानीग्राही कहा कि वे इस फिल्म को अभी रिलीज नहीं करने वाले थे लेकिन कलाकारों की जिद के आगे वे हार गए क्योंकि उनका कहना था कि अक्टूबर माह में आचार सहिता लग जाएगा और वे सभी कलाकार राजनीतिक पार्टियों के प्रचार-प्रसार में जुट जाएंगे। वैसे भी यह समय फिल्म लगाने का सही समय नहीं है क्योंकि एक तरफ बारिश होते रहती है और दूसरा कारण तीज और त्यौहार। अक्टूबर से जनवरी के बीच फिल्मों को देखने ज्यादा पसंद करते हैं लोग। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छालीवुड में फिल्म इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि यहां पर सिनेमाघरों की बहुत कमी है और मल्टीप्लेक्सों में फिल्म लगाने के लिए निर्माता के पास इतना बजट नहीं होता कि वह उसे वहन कर सकें। हम सभी कलाकार छालीवुड इंडस्ट्रीज की तरफ से राज्य सरकार से मांग करते है कि वे प्रत्येक जिले में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी एक मिनी थियेटर खोलने की अनुमति दे दी ताकि गांव के लोग उसे देखने ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें। वर्तमान हो यह रहा है कि राज्य में कितनी के सिनेमाघर है और अधिक पैसा खर्च कर वे फिल्में देखना नहीं चाहते है अगर मिनी थियेटर गांव के आसपास खुल जाएगा तो वे 20 रुपये खर्च आसानी से फिल्में देखने पहुंचे और एक दिन में 10 हजार रुपये की कमाई होती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ में बनेगी 75 सीटो के साथ कांग्रेस सरकार: बैज

रायपुर। भिलाई में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा में प्रदेश भर से आई लाखो की संख्या में उमड़े महिलाओं के हूजुम ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवाओं के बाद महिलाओं ने भी भूपेश सरकार पर अपना भरोसा जताया है। प्रदेश के हर वर्ग के भरोसे से यह साफ हो गया कि राज्य में एक बार फिर से 75 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2018 में दो तिहाई बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार के कार्यो का परिणाम है कि कांग्रेस के प्रति तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ता ही जा रहा है। 5 सालो में 5 उपचुनावो, 10 महापौर सहित अधिकांश नगर निकायो तथा पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस को भरपूर आर्शीवाद दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राज्य में शिक्षा, रोजगार, कृषि, आदिवासी, अनुसूचित जाति हर वर्ग के बढ़ावे के लिये काम किया है। सभी के लिये योजना बनाया और उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, जिससे राज्य के गरीब आदमी के जीवन स्तर में परिवर्तन आया तथा 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आये। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है।

छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन

रायपुर। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव के द्वारा जारी आदेशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के नियम 34(2) के अधीन राज्य में ऐसे दिव्यांग जो अधिक सहारे की आवश्यकता वाले हों, ऐसे विशेष प्रकरणों की प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रकरण का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना होगा। निर्धारण बोर्ड में कलेक्टर या प्रतिनिधि(अतिरिक्त/ संयुक्त कलेक्टर से अन्यून) को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/उपसंचालक को सदस्य/ सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी। जारी आदेशानुसार अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। वह निर्धारण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान किया जाए। वित्तीय एवं अन्य संसाधानों की उपलब्धता के आधार पर संयुक्त/उपसंचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

प्रियंका जी, पुरखों के किस्से न सुनाएं,: सरोज पांडेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों के जवाब में कहा कि वे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की भाषा बोल रही हैं। जहां से फर्जी आंकड़े भूपेश बघेल को मिलते हैं, वहीं से मिले आंकड़े गिना कर प्रियंका गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के बारे में बताने लायक उनके पास कुछ नहीं था इसलिए वे यूपी के उस जमाने के किस्से कहानी सुना गईं जब उनके पिता प्रधानमंत्री थे। पिता तो पिता वे अपने पिता के नाना तक की लोरियां छत्तीसगढ़ की बहनों को सुना गईं। उनके पास पुरखों के संस्मरण सुनाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वे स्वयं स्वीकार कर गईं कि उनके पिता प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी सड़क तक नहीं दे सके। इससे गई गुजरी बात और क्या हो सकती है। प्रियंका आज के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को देखें। रही बात गैस सिलेंडर की तो बतायें कि वे चार सिलेंडर कहां हैं, जो 2018 के जन घोषणा पत्र में कांग्रेस दे रही थी।छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है तो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लड़ना चाहिए कि किस बात का महिला समृद्धि सम्मेलन कर रहे हैं। महिलाओं को समृद्ध बनाने उन्होंने किया क्या है? एक तरफ महिलाओं की अस्मिता खतरे में है,।

सरोज के संघी पूर्वज अंग्रजों की मुखबिरी करते थे : शुक्ला

रायपुर। भजपा नेत्री सरोज पाण्डेय के बयान की प्रियंका गाँधी नें अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला नें कहा देश की आजादी की लड़ाई से लेकर भारत के नवनिर्माण तक मे प्रियंका गाँधी के पूर्वजों की कहानिया इतिहास मे भरी पड़ी हैं प्रियंका गाँधी के पिता राजीव गाँधी,दादी इंदिरा गाँधी पिता के नाना पंडित जवाहर लाल नेहरू पर नाना मोतीलाल नेहरू सभी नें देश के लिए कुर्बानी दिया हैं। देश की आजादी की लड़ाई मे अपना सर्वश्व न्योछावर किया हैं।जिस भिलाई मे प्रियंका गाँधी सभा कर रही थी उसको भिलाई इस्पात संयत्र का तोहफा प्रियंका के परनाना देश के पहले प्रधान मंत्री नेहरू जी ने दिया हैं। सरोज पाण्डेय के दल के पितृ संगठन के लोगो का इतिहास दरिद्र हैं इसलिए उन्हें दूसरे के वैभवशाली और बलिदानी इतिहास से जलन हो रही। ज़ब पंडित जवाहर लाल नेहरू देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे तब सरोज के संघी पूर्वज अंग्रेजो की जी हुजूरी के देश की आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे आज भाजपा देश की आजादी और भारत के नव निर्माण की बाते सुन कर अनर्गल बाते कर रही हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला नें कहा की भाजपा की केंद्र सरकार जिन सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही हैं उन सबको देश की जरूरतों को ध्यान मे रख कर प्रियंका के पूर्वजों कांग्रेस के नेताओं नें बनाया था। सरोज बताये मोदी सरकार नें पिछले 9 साल मे एक भी सार्वजनिक इकाई क्यों नहीं लगाया

विश्वसनीय के संकट से जूझ रहे हैं भाजपाई: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के परिवर्तन यात्रा को न केवल जनता, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी नकार दिया है। बाहर से बुलाए गए नेताओं के भरोसे निकल गई परिवर्तन यात्रा का भाजपा के ही स्थानीय कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे हैं, लोगों की भीड़ कहीं नहीं आ रही है, उल्टे हर जगह इनकी गुटबाजी सामने आ रही है। जमीनी हकीकत यही है कि भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नीति, नीयत, नेता और विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों, नड्डा सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीयों के कार्यक्रम भी पूरी तरह से असफल साबित हुए। इनकी कोरी लफ्फाजी और तथ्यहीन आरोपों से भाजपा के झूठा, भ्रम और वादा खिलाफी ही हर बार उजागर हुआ है। 2018 की तरह ही छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भी भाजपाइयों पर भरोसा नहीं कर रही है।2018 में विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी जी 4-4 बार छत्तीसगढ़ आए थे, परिणाम सर्वविदित है। अमित शाह ने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को 65 प्लस का नारा दिया, लेकिन हुआ उल्टा 15 साल के कुशासन के बाद भाजपाई 15 सीट में सिमट गई, आज इनके कुल 13 विधायक ही बचे हैं।

किसानों और भूमिहीन मजदूरों को मिलेगी इसी माह न्याय योजना की तीसरी किश्त

रायपु। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के किसानों राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान सितम्बर माह की आखिर तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात आज दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला अगले माह अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के परिप्रेक्ष्य में लिया है। गौरतलब है कि उक्त दोनों योजनाओं की तीसरी किश्त का भुगतान अब तक राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को किया जाता रहा है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग 24.43 लाख किसानों को दो किश्तों में 3704 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को प्रथम किश्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई 2023 को 1894.93 करोड़ रूपए तथा द्वितीय किश्त की राशि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2023 को 1810 करोड़ रूपए प्रदान की गई थी। तीसरी किश्त की राशि लगभग 1890 करोड़ रूपए किसानों के बैंक खातों में इस माह के आखिर तक जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा इसको लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाना तथा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई और इसका लाभ खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक किसानों को देने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2020 में इस योजना के तहत किसानों को 5627 करोड़ रूपए, वर्ष 2021 में 5553 करोड़ रूपए, वर्ष 2022 में 7028 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2023 की दो किश्तों में अब तक 3704 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब तक 21913 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है।

23-24 सितंबर तक 8 ट्रेनें फिर कैंसिल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 300 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को बीते दो माह के भीतर कैंसिल किया गया है। इस बार फिर रेल प्रशासन ने ऑटो सिग्नलिंग काम के नाम पर 22 और 23 सितंबर को 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है।बिलासपुर जोन के साथ ही दूसरे रेलवे जोन में दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन का काम चल रहा है। लेकिन विकास कार्यों के बहाने हर सप्ताह यात्री ट्रेनों लगातार कैंसिल हो रहीं हैं। वहीं यात्री ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

छत्तीसगढ़ के रूट से चलने वाली ट्रेनों को कभी ट्रैक पर निर्माण कार्य तो कभी सुरक्षा संबंधी रखरखाव के बहाने कैंसिल किया जा रहा है। वहीं, माल लदान में हर साल रिकॉर्ड बनाने के लिए कोयला परिवहन जारी है।

रेल प्रशासन ने अगस्त के पहले सप्ताह से ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला शुरू किया है, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बारिश के दौरान सुरक्षा संबंधी रखरखाव के नाम से भी 50 से अधिक यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। वहीं, दूसरी व तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के बहाने गाड़ियों को कैंसिल किया जा रहा है। इस बार बिलासपुर मंडल के जयरामनगर, लटिया और अकलतरा में कार्य किया जाएगा। इस रूट की यात्री ट्रेनें पहले से ही रद्द चल रही हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। रेल प्रशासन का दावा है कि ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली लागू होने से एक ही सेक्शन में कई गाड़ियो को थोड़े अंतराल पर ही चलाया जा सकता है, जिससे सेक्शनों की परिचालन क्षमता बढ़ जाती है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.